₹5/

ग्लोबल ऑब्ज़र्वर

मतलब निर्भीक और निष्पक्ष | इस छोर से उस छोर तक

RNI NO. DELHIN/2016/71079

राष्ट्रीय साप्ताहिक | वर्ष : 09, अंक : 22 | 23-29 जून, 2025

समाजसेवी महेन्द्र यादव एडवोकेट को शेर ए दिल्ली चौधरी ब्रह्म प्रकाश यादव शिखर सम्मान

ग्लोबल ऑब्ज़र्वर

मतलब निर्भीक और निष्पक्ष

इस छोर से उस छोर तक

RNI NO. DELHIN/2016/71079

ग्लोबल ऑब्ज़र्वर पढ़ें और पढ़ाएं

एक शुभचिंतक, दिल्ली

‘हम पत्रकार हैं हुज़ूर, जंग में भी ख़बर लिखते हैं’

ओंकारेश्वर पांडेय

‘आदाब-ओ-तहियात... मैं हूं सहर एमामी... और इस वक़्त आप देख रहे हैं आईआरआईबी का ख़ास ब्रॉडकास्ट – आज फिर इज़्राइली हमलों ने हमारे वतन को लहू-लुहान किया है... कई मासूम ज़ख़्मी हैं... और अफ़सोसनाक तौर पर, मौत की ख़बरें भी तस्दीक़ हो रही हैं... हम आपको दे रहे हैं ताज़ा-ओ-मुहिम ख़बरें, सीधा तेहरान से...’

यह शब्द उस वक्त गूंज रहे थे जब ईरान के सरकारी चैनल IRIB (Islamic Republic of Iran Broadcasting) की एंकर सहर एमामी लाइव बुलेटिन में थीं। कैमरा चल रहा था, बुलेटिन जारी था, और तभी...

एक जोरदार धमाका – स्क्रीन थर्रा गई, कैमरा डगमगा गया। स्टूडियो की छत कांपी, और एक पल के लिए जैसे हर सांस थम गई।

यह एक इस्राइली मिसाइल हमला था – और वो भी ऐन उसी वक्त, जब सहर एमामी पूरी दुनिया को जंग की खबरें दे रही थीं।

सन्नाटा... फिर लौटी आवाज

चंद लम्हों के लिए प्रसारण रुका, लेकिन सहर एमामी का हौसला नहीं। कुछ ही मिनटों बाद वही ऐंकर फिर कैमरे पर लौटीं – शायद कांपते हाथों से माइक संभाला हो लेकिन आवाज में फिर वही स्थिरता, वही समर्पण।

‘ये ऐंकर नहीं, हिम्मत की आवाज थी’

जब मिसाइलें गिर रही हों, दीवारें डोल रही हों, और फिर भी कोई सच को जनता तक पहुंचाने के लिए लौट आए – तो वो सिर्फ़ पत्रकार नहीं, ज़िंदा इतिहास होती हैं।

उनकी आंखों में डर नहीं था, बस ज़िम्मेदारी थी। उनके शब्द किसी हथियार से कम नहीं थे।

‘ख़ामोशी भी चीख़ उठती है जब एक औरत हथियारों के बीच सच बोलती है।’ – एक दर्शक की टिप्पणी-

सहर – सुबह की पहली रौशनी

नाम के मुताबिक, सहर एमामी ने अंधेरे के बीच रौशनी की मिसाल पेश की। उन्होंने मिसाइलों की बारिश में भी पत्रकारिता का सूरज बुझने नहीं दिया।

‘गर जवाब न दे सको, तो आवाज़ तो दो...’

सहर की आवाज़ वही जवाब थी।

ईरान की बेटी, जंग की रिपोर्टर

तेहरान के गलियों से लेकर सोशल मीडिया तक, हर ओर एक ही नाम था – सहर एमामी। लोग उन्हें कह रहे हैं:

ईरान की बेटी

हौसले की सदा

‘जब स्टूडियो बना रणभूमि, तब ऐंकर बनी आवाज़-ए-हक़’ – फ़ैज़ान रिज़्वी, वरिष्ठ पत्रकार

दुनियाभर की प्रतिक्रिया-

बीबीसी: ‘ब्रॉडकास्टिंग इतिहास का असाधारण क्षण’

पत्रकारिता की मिसाल

‘शोर-ए-गुल से न दब जाए कोई सदा-ए-हक, हम वो सदा हैं जो तिलिस्म-ए-खौफ तोड़ते हैं।’

सहर एमामी की वापसी सिर्फ हिम्मत नहीं थी, यह उस पत्रकारिता की मिसाल थी, जहां एक औरत, एक क़लमकार, एक रिपोर्टर, अपनी जान की परवाह किए बिना अपने फ़र्ज़ को अंजाम देती है।

जंग के मैदान से लाइव रिपोर्टिंग नई बात नहीं है। लेकिन इस तरह लाइव टेलीविजन स्टूडियो पर मिसाइल हमला और फिर भी उसी ऐंकर का लौटना – यह दृश्य पूरी दुनिया में पहली बार देखा गया है।

2003: Reuters के मैजेन दाना की मौत बगदाद में

2014: गाजा में सिनोमी कैंमीली और अली अबू अफाफ की मौत

मगर 2025 की तेहरान की इस रात – वो अलग थी क्योंकि इस रात क़लम और कैमरा बमों से भी न डरे।

मध्य पूर्व में पत्रकारिता का ख़तरा

CPJ रिपोर्ट (2024): 124 पत्रकार मारे गए, जिनमें 70% इस्राइल-गाजा युद्ध क्षेत्र से

IFJ रिपोर्ट: मध्य पूर्व में 77 पत्रकारों की जान गई

गाजा: अकेले 178 पत्रकार शहीद – 21वीं सदी का सबसे बड़ा ख़ूनख़राबा पत्रकारिता में

‘ग़म-ए-हयात का क्या शिकवा करें, जब क़लम चलती है तो बम भी थम जाते हैं।

ईरानी महिला पत्रकारों की परंपरा

ईरान में महिला पत्रकारों ने सदियों से सत्ता, समाज और सेंसरशिप के सामने डटकर लिखा और बोला है। हिजाब के भीतर से भी आवाजें उठती रहीं – जो न्याय, अधिकार और स्वतंत्रता की मांग करती रहीं।

‘हमारी आवाज़ें बंदूकों से बुलंद हैं।’

सहर एमामी – एक नाम नहीं, प्रतीक

उनकी वापसी एक पैग़ाम थी – कि पत्रकारिता सिर्फ़ पेशा नहीं, ज़िम्मेदारी है। और ये ज़िम्मेदारी तब सबसे बड़ी हो जाती है, जब हर लफ़्ज़ मौत की नज़र में हो।

सहर एमामी आज एक रिपोर्टर नहीं, एक मशाल बन गई हैं – जो झुलसती ज़मीन पर भी सच का उजाला लेकर खड़ी हैं।

‘जब मिसाइल गिरे तब भी वो ख़बरों की ज़ुबान बनी रही...’

यह पंक्ति महज़ सहर एमामी नहीं, हर उस पत्रकार को सलाम है, जो बमों की गूंज में भी सच्चाई की गूंज बनाए रखते हैं।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार, और यूनेस्को से संबद्ध थिंक टैंक गोल्डेन सिगनेचर्स के संस्थापक हैं।)

ग्लोबल ऑब्ज़र्वर
मतलब निर्भीक और निष्पक्ष
इस छोर से उस छोर तक
RNI NO. DELHIN/2016/71079
वर्ष : 09, अंक : 22
23-29 जून, 2025

संपादक
ए आर आज़ाद

ब्यूरो प्रमुख
रुफी शमा

बेगूसराय ब्यूरोचीफ
एस आर आज़मी

ब्यूरो ऑफिस बिहार
बजरंगबली कॉलोनी, नहर रोड,
जज साहब के मकान के सामने, फुलवारी शरीफ,
पटना, बिहार-801505

संपादकीय एवं पंजीकृत कार्यालय
81-बी, सैनिक विहार, फ़ेज़-2, मोहन गार्डेन,
उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059
Email: globalobserverindia@gmail.com
MOBILE. 9810757843
Whatsapp. 9643709089

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक
ए आर आजाद द्वारा 81-बी, सैनिक विहार, फ़ेज़-2, मोहन गार्डेन, उत्तम नगर, नयी दिल्ली-110059 से प्रकाशित एवं चंद्रशेखर प्रिंटर्स, डब्लू जेड-439, नारायणा विलेज, नई दिल्ली-110028 से मुद्रित।
संपादक- ए आर आज़ाद

RNI NO.: DELHIN/2016/71079
Email:globalobserverindia@gmail.com

समाचार-पत्र में छपे सभी लेख, लेखकों के निजी विचार हैं, इनसे संपादक या प्रकाशक का सहमत होना अनिवार्य नहीं। समाचार-पत्र में छपे लेखों के प्रति संपादक की जवाबदेही नहीं होगी। सभी विवादों का समाधान दिल्ली की हद में आने वाली सक्षम अदालतों में ही होगा। *उपरोक्त कुछ पद अवैतनिक हैं।*

आवरण 16

महेन्द्र यादव एडवोकेट को शेर ए दिल्ली चौधरी ब्रह्म प्रकाश यादव शिखर सम्मान

दृष्टिकोण 06

जस्टिस वर्मा.....

पड़ताल 12

महिलाओं का हिंसक दौर...

बेबाक 18

एयर इंडिया...

प्रसंगवश 24

बेगूसराय कांग्रेस ने कसी कमर

नज़रिया 22

उच्च शिक्षा में गिरावट

संपादकीय

इस ट्यून पर अदालतें संज्ञान लें

देश की जनता को अब जुल्म के ख़िलाफ़ स्वर मुखर करना चाहिए। यह भी एक जुल्म ही है। आप जिसे नहीं चाहते हों, या जो आपकी धड़कनें बढ़ा दे, उसे स्वीकार किसी क़ीमत पर नहीं करना चाहिए। यह ट्यून देश हित में नहीं, बल्कि देश वासियों के लिए जी का जंजाल बन चुका है। इस पर सुप्रीम कोर्ट तो संज्ञान लेना ही चाहिए था। और देश की विभिन्न कोटि की अदालतों का भी ध्यान अवश्य जाना चाहिए था। लेकिन जब जगे, तभी सवेरा। अभी भी वक़्त है, अदालतें संज्ञान लें।

मोबाइल कॉल करना अब आसान नहीं रह गया है। अब हर एक कॉल सभी को सालने लगा है। ये ट्यून तब और सालती है, जब आपको बहुत जल्दी है। किसी से आपको बहुत ज़रूरी बात करनी है। आप छटपटाकर रह जाएंगे। आप छटपटाते रहेंगे, लेकिन अमिताभ बच्चन अपनी बातें पूरी किए बिना दम नहीं लेंगे। यह कैसी विडम्बना है कि हम अनचाहे कॉल ट्यून से निजात नहीं पा सकें। आप कॉल काटकर फिर दोबारा-तीबारा लगाने की कोशिश कर लें, लेकिन फिर भी वही ट्यून आपके कानों के परदा फाड़ने के लिए आतुर दिखेगा। कोरोना काल में तो लोगों ने अनचाहे कॉल ट्यून को लाचारी, बेबसी और बेचारगी में स्वीकार कर लिया था। लेकिन आज जिस तरह से ये ट्यून समय की बर्बादी और ज़रूरी चीज़ों में ख़लल का सबब बन गया है, वे हमारी व्यवस्था और सरकार की अदूरदर्शिता को दर्शाता है।

साइबर ठगी और धोखाधड़ी जैसे मामले से निपटने के लिए जो व्यवस्था दी गई है, वह बेहद ही भोंडा और लापरवाही भरा है। इस देश को अगर समय की क़ीमत नहीं मालूम, तो फिर किसे मालूम होगा? इस देश में 30 सेकेंड मायने रखता है। इस 30 सेकेंड में कितने की दुनिया तबाह हो जाती है। और हो सकती है।

इस बार तो महानायक के बोल में संजीदगी नहीं दिखती है। ठगी पर न तो वाक्य और न ही लहजे सही हैं। कहीं से नहीं लगता कि इसकी देश को ज़रूरत भी है। ठगी पर सचेत करने के और भी उपाय सरकार तलाश सकती थी। लेकिन इतने लंबे समय तक इसे जनता को झेलने के लिए विवश करना, कहीं से भी समझदारी नहीं कही जा सकती है। सरकार को अगर अमिताभ बच्चन की आर्थिक या दूसरी मदद ही करनी थी, तो और भी बहुत सारे उपाय और सरकार के पास संसाधन थे। लेकिन सरकार ने अपनी मनमानी करने का एक और नुस्ख़ा तलाश लिया। और यह जांचने की कोशिश कर रही है कि हम जनता जनार्दन पर जो भी बोझ डालेंगे, वे उसे सहर्ष स्वीकार है कि नहीं! यही परख करने की लालसा ने कई हुकूमत की अब तक बैंड बजा चुकी है।

माना कि भारत की जनता की सहनशक्ति असीम है। असीम हो भी क्यों नहीं। एक लंबे समय तक ग़ुलामी की ज़ंज़ीर में जो जकड़ी रही है। दासता की चाकरी करती रही। लेकिन देश को ग़ुलामी से निजात मिले भी एक लंबा अरसा हो चुका है। इस लंबे अंतराल के बाद जनता को उसी ग़ुलामी का एहसास कराना, किसी भी लोककल्याणकारी सरकार के लिए उचित नहीं है।

भारत की अपनी गरिमा रही है। और जिन बादशाहों ने भी भारत की गरिमा से खिलवाड़ किया, उसे यहां के लोगों की सब्र और उनके धैर्य ने सिंहासन पर टिकने नहीं दिया। उनका सिंहासन बिना भूकंप के डोलने लगा। इसलिए किसी भी सरकार को लोककल्याणकारी सरकार होना चाहिए। वरना इतिहास उनको बदनामी के क़ैद में और निरंकुश शासक के तौर पर एक पेज देने के लिए हमेशा उत्साहित रहता है।

देश की जनता को अब जुल्म के ख़िलाफ़ स्वर मुखर करना चाहिए। यह भी एक जुल्म ही है। आप जिसे नहीं चाहते हों, या जो आपकी धड़कनें बढ़ा दे, उसे स्वीकार किसी क़ीमत पर नहीं करना चाहिए। यह ट्यून देश हित में नहीं बल्कि देश वासियों के लिए जी का जंजाल बन चुका है। इस पर सुप्रीम कोर्ट को तो संज्ञान लेना ही चाहिए था। और देश की विभिन्न कोटि की अदालतों का भी ध्यान अवश्य जाना चाहिए था। लेकिन जब जगे, तभी सवेरा। अभी भी वक़्त है, अदालते संज्ञान लें।

रामस्वरूप रावतसरे
स्तंभकार

जस्टिस वर्मा को आरोप मुक्त करा देगें क्या कपिल सिब्बल

सुप्रीम कोर्ट की एक 3 जजों की कमेटी ने जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने की सिफारिश पेश की है। इसके बाद जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। यह सिफारिश 64 पेज की एक रिपोर्ट में की गई है जिसे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजा गया है। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि जले हुए नोट जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास के स्टोररूम में ही मिले थे। इसी मामले में भ्रष्टाचार के आरोप में फँसे जस्टिस यशवंत वर्मा का सपोर्ट वकील कपिल सिब्बल ने किया है। कपिल सिब्बल ने कहा कि जस्टिस वर्मा अब तक के सबसे बेस्ट जजों में से एक है।

जांच कमेटी के अनुसार स्टोररूम तक सिर्फ जस्टिस वर्मा और उनके परिवार की ही पहंच थी, किसी बाहरी व्यक्ति की नहीं थी। जांच में सामने आया है कि आग बुझाने के दौरान फायरफाइटर्स ने 'आधे जले हुए नोट' देखे थे। एक गवाह ने तो यहां तक कहा कि उसने जिंदगी में पहली बार इतना ज्यादा कैश का पहाड़ देखा था। कमेटी ने माना है कि इतने सारे नोट बिना जस्टिस वर्मा या उनके परिवार की मर्जी के वहाँ नहीं रखे जा सकते थे। कमेटी ने जस्टिस वर्मा की बेटी दिया वर्मा और उनके निजी सचिव राजिंदर कार्की की भूमिका की भी जाँच की है जिन पर आरोप है कि उन्होंने फायरफाइटर्स को कैश की जानकारी किसी को भी बताने को मना किया था। इन सभी बातों के आधार पर कमेटी ने कहा है कि जस्टिस वर्मा को पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं।

हालांकि, जस्टिस वर्मा ने इन आरोपों से इंकार करते हुए कहा कि उन्हें या उनके परिवार को इस कैश के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जस्टिस वर्मा ने यह भी कहा था कि स्टोररूम में कोई भी आ-जा सकता था। जून 2025 महीने की शुरूआत में खबर आई थी कि जस्टिस वर्मा को हटाने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो सकती है। यह भारत के इतिहास में किसी सिटिंग जज को जबरन हटाने का पहला मामला होगा।

जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा केस में एक जाँच कमेटी बनाई थी। प्रकरण में जांच कमेटी ने 55 गवाहों से पूछताछ की थी। इसमें जस्टिस वर्मा की बेटी दिया वर्मा भी शामिल थीं। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि कई गवाहों, वीडियो और तस्वीरों से यह साबित होता है कि जस्टिस वर्मा के दिल्ली वाले घर के स्टोररूम में बड़ी मात्रा में कैश खासकर 500 रुपए के नोट मिले थे जिनमें से कुछ आधे जले हुए थे। इतनी बड़ी घटना के बावजूद ना तो जस्टिस वर्मा और ना ही उनके परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी और ना ही किसी बड़े ज्यूडिशियल ऑफिसर को इसकी जानकारी दी थी। कमेटी ने इसे विचित्र व्यवहार बताया। जांच कमेटी ने यह साफ किया कि जस्टिस वर्मा को जले हुए कैश की जानकारी ना होने का दावा करना एक अविश्वसनीय है। कमेटी ने सवाल किया, 'अगर कोई साजिश थी, तो जस्टिस वर्मा ने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या भारत के चीफ जस्टिस को सूचित क्यों नहीं किया?'

फायर और पुलिस कर्मियों ने भी बताया कि उन्होंने आग बुझाने के बाद स्टोररूम में 500 रुपए के नोटों का 'बड़ा पहाड़' देखा था। हालांकि, घर के नौकरों ने कैश देखने से मना किया पर कमेटी ने सरकारी अधिकारियों के बयानों को सच माना। जांच में यह भी सामने आया कि जिस स्टोररूम में आग लगी थी, उसका कंट्रोल केवल और केवल जस्टिस वर्मा और उनके परिवार के पास था। इसके अलावा घटना के बाद कथित तौर पर जला हुआ कैश 'गायब' हो गया और कमरा साफ कर दिया गया।

जांच कमेटी के अनुसार जस्टिस वर्मा के निजी सचिव राजिंदर सिंह कार्की ने फायर ऑफिसर को कहा था कि वे अपनी रिपोर्ट में कैश का जिक्र न करे। फायर सर्विस के ऑफिसर ने यह भी दावा किया था कि उन्हें इस मामले को आगे न बढ़ाने के लिए कहा गया था क्योंकि इसमें 'ऊपर के लोग शामिल थे।'

मार्च 2025 में, दिल्ली में जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास में आग लग गई थी। आग बुझाने के दौरान फायरफाइटर्स को स्टोररूम में जले हुए 500 रुपए के नोटों का एक बड़ा पहाड़ मिला था। इस घटना के बाद तत्कालीन सीजेआई ने जस्टिस वर्मा पर आरोप लगाए थे। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच के लिए एक कमेटी बनाई थी। जस्टिस वर्मा को इस घटना के कुछ ही दिनों बाद दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया था। ऐसा

करने पर कुछ वकीलों और लीगल वर्कर्स ने इसका विरोध किया था।

जस्टिस यशवंत वर्मा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया था। कमेटी ने 55 गवाहों से पूछताछ की और जस्टिस वर्मा का बयान दर्ज किया है। कमेटी ने अपनी 64 पेज की रिपोर्ट राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को सौंपी थी, जिसमें जस्टिस वर्मा को पद से हटाने की सिफारिश की गई थी। जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया है लेकिन उन्हें कोई ज्यूडिशियल काम नहीं सौंपा गया है। जस्टिस वर्मा ने अभी तक ना तो इस्तीफा दिया है और ना ही वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया है। अब संसद में उनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना जताई जा रही है, जो भारत में किसी सिटिंग जज को हटाने का पहला मामला होगा।

जस्टिस वर्मा ने जाच को 'फंडामेंटल रूप से गलत' बताया है लेकिन कमेटी ने उनके बचाव को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि 'करेंसी नोट कई लोगों ने देखे और वास्तविक समय में रिकॉर्ड किए गए। यह असंभव है कि उन्हें फंसाने के लिए लगाया गया हो' कमेटी ने सबूत हटाने या घटनास्थल को साफ करने में उनकी बेटी और निजी सचिव की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं।

वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने इस मामले में जस्टिस यशवंत वर्मा का बचाव किया है। 17 जून्र, 2025 को सिब्बल ने जस्टिस वर्मा को 'सबसे बेहतरीन जजों में से एक' बताया और सरकार की इस कार्रवाई की आलोचना की है। सिब्बल का आरोप है कि सरकार का असली मकसद कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करना और न्यायिक नियुक्तियों पर कंट्रोल पाना है। सिब्बल ने सरकार पर आरोप लगाया कि वह जस्टिस वर्मा के खिलाफ तो मामला चला रही है लेकिन जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ ऐसी ही कार्रवाई नहीं कर रही है। जस्टिस शेखर यादव पर पिछले साल कुछ 'सांप्रदायिक' टिप्पणियों के आरोप लगे थे और उनके खिलाफ विपक्ष के सांसदों ने महाभियोग का नोटिस भी दिया था।

सिब्बल ने कहा, 'मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि वह (वर्मा) सबसे बेहतरीन जजों में से एक हैं जिनके सामने मैंने बहस की है। आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के किसी भी वकील से पूछ लें, इस जज पर कोई गलत काम करने का आरोप नहीं है।' सिब्बल ने ागे कहा, 'यह चौंकाने वाला है कि आप (सरकार) एक ऐसे जज को निशाना बना रहे हैं जिसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है और आप एक ऐसे जज की रक्षा कर रहे हैं जिसके खिलाफ सबूत की जरूरत नहीं है क्योंकि उनका बयान सार्वजनिक डोमेन में है और अध्यक्ष के पास एक महाभियोग प्रस्ताव लंबित है और वह हस्ताक्षर सत्यापन के लिए इस पर बैठे हैं।'

वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल जस्टिस यशवंत वर्मा के पक्ष में जो कुछ भी कह रहे है। यदि वह सही है तो क्या तीन जजों की जांच रिपोर्ट गलत है, सरकार प्रेरित है। आखिर ये जांच कमेटी के निर्णय के इतर जाकर जस्टिस वर्मा का किन कारणों से पक्ष ले रहे है? बहरहाल हमारे यहां सभी को अपना पक्ष रखने का संवैधानिक अधिकार है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

ll ललित गर्ग
स्तंभकार

ईरान और इजरायल युद्ध

हिंसा, युद्ध, आतंकवाद, आर्थिक प्रतिस्पर्धा से त्रस्त दुनिया में क्या अब शांति एवं अमन की संभावनाओं पर विराम लग गया है? क्या शांतिपूर्ण नये विश्व की संरचना अब दिवास्वप्न है? रूस और यूक्रेन के लम्बे युद्ध के बाद इजराइल और ईरान का युद्ध विश्व के लिये महाविनाश की टंकार है। इस युद्ध के खतरे बढ़ते ही जा रहे हैं। अब तक के कई दिनों के युद्ध में ईरान और इजरायल में सैकड़ों की मौत, हजारों घायल, अरबों का नुकसान, दुनिया में अनिश्चिंतता एवं भय का माहौल, तेल की बढ़ती कीमतों से महंगाई बढ़ने की आशंका ने समूची दुनिया को डरा रखा है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को गंभीर नुकसान पहुंचा है, लेकिन नष्ट नहीं किया गया है। अमेरिका और इजराइल का मानना है कि ईरान ने परमाणु बम बनाने की क्षमता हासिल कर ली है और अगर अब उसे नहीं रोका गया, तो खतरा पूरी दुनिया को होगा। इजराइल इसी खतरे को मिटाने की बात कहकर ईरान पर तीव्र से तीव्रत्तर हमले कर रहा है। और ईरान भी जबावी हमलों में इजरायल में तबाही मचा रखी है। युद्ध भले ही इन दो देशों के बीच हो रहा है, लेकिन उसका प्रभाव समूची दुनिया पर हो रहा है। इस संघर्ष को रोकना आवश्यक है, भले ही अमेरिका अभी तक मैदान में नहीं उतरा। और यूरोप अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। इस युद्ध को रोकने के लिए बातचीत ही एकमात्र रास्ता है।

ईरान और इजरायल संघर्ष की वजह से दुनिया में अनिश्चिंतता एवं अस्थिरता के बादल मंडरा रहे हैं। विशेषतः तेल के दाम आसमान छूने लगे हैं। पिछले दिनों क्रूड ऑयल के दाम में एक ही दिन में पिछले तीन साल की सबसे बड़ी तेजी देखी गई है। दोनों देश एक-दूसरे के ऊपर मिसाइलों से हमला कर रहे हैं, परमाणु युद्ध की आशंकाएं उग्र होती जा रही है। दोनों देशों के बीच फिलहाल इस युद्ध के रुकने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। तेल की बढ़ती कीमतों ने भारत समेत दुनियाभर के लिए संकट पैदा कर दिया है। क्रूड ऑयल की ग्लोबल डिमांड का 2 प्रतिशत ईरान से आता है। यहां के खरग द्वीप से करीब 90 प्रतिशत तेल बाहर भेजा जाता है। सैटेलाइट इमेज से पता चलता है कि क्रूड शिपमेंट में कमी आई है। पूर्ण युद्ध की स्थिति में ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद कर सकता है। इससे होकर दुनिया की 20 प्रतिशत नेचुरल गैस और एक तिहाई तेल ट्रांसपोर्ट होता है। यह रूट बाधित हुआ तो कच्चे तेल में 20 प्रतिशत तक उछाल आ सकता है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के अनुसार इराक, सऊदी अरब, कुवैत और यूएई से आने वाला कच्चा तेल, जो होर्मुज से होकर गुजरता है, भारत के कुल कच्चे तेल के आयात का लगभग 45-50 प्रतिशत है। एक तथ्य यह भी है कि ईरान भी जानबूझकर तेल की कीमतों को आसमान छूने के लिए मजबूर करके ट्रम्प प्रशासन को अस्थिर करने की कोशिश कर सकता है। और पश्चिमी देशों में मुद्रास्फीति बढ़ा सकता है।

ईरान और इजरायल के युद्ध के जटिलतर एवं घातक होते जाने के ही संकेत मिल रहे हैं। इजरायल चाहता है कि ईरान में सत्ता परिवर्तन हो और अयातुल्ला अली खामेनेई के शासन का अंत हो। हालांकि इस बात की गारंटी डॉनल्ड ट्रंप या नेतन्याहू में से कोई नहीं ले सकता कि खामेनेई को हटाने से समस्या का समाधान हो जाएगा। यह कैसे कहा जा सकता है कि नई सत्ता को परमाणु ताकत बनने में कोई दिलचस्पी नहीं होगी, वह भी जब उसके पास अमेरिका और इजरायल के हिसाब से जरूरी साधन मौजूद हैं। इन हवाई हमलों से या जमीन पर सीधी लड़ाई लड़कर भले ही ईरान के इन्फ्रास्ट्रक्चर को खत्म कर दिया जाए, लेकिन ईरान के उस तकनीकी ज्ञान को कैसे खत्म किया जा सकता है, जो ईरानी वैज्ञानिकों ने बरसों की मेहनत से हासिल की है। ऐसे में विदेशी दबाव में हुआ बदलाव ईरान को और ज्यादा कट्टरता की ओर ही ले जाएगा। ऐसे में अमेरिका या इजराइल के हमलों से ईरान में आमूल-चूल परिवर्तन होना संभव प्रतीत नहीं होता।

इराक, लीबिया, सीरिया - कई उदाहरण हैं, जहां पश्चिमी ताकतों ने अपने हिसाब से बदलाव लाने के प्रयास किए, लेकिन इनमें से कहीं भी नतीजा मन-मुताबिक एवं सफल-सार्थक नहीं रहा। ये देश आज भी अस्थिर हैं। तेहरान को लेकर कोई भी दुस्साहस ईरान को भी इन्हीं मुल्कों की श्रेणी में ला सकता है। ऐसी स्थितियों में कैसे बदलाव की आशा की जा सकती है?

अमेरिका हो या इजरायल, ईरान या दुनिया की अन्य महाशक्तियों उनकी तरफ से ऐसी कोई पहल होती हुई नहीं दिख रही है, जिससे लगे कि वे यह संघर्ष टालना चाहते हैं। इजराइल का कहना है कि वह ईरान की परमाणु हथियार बनाने की क्षमता को खत्म करने के लक्ष्य को हासिल होने तक युद्ध नहीं रोकेगा, लेकिन क्या ऐसा संभव है? ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का कहना है कि कोई भी बातचीत इजराइली हमले रुकने के बाद ही होगी। दोनों देशों की जिद्द एवं अकड़ से प्रतीत नहीं होता कि शांति एवं युद्ध विराम का रास्ता संभव है।

वैसे, इजराइल ने पिछले 15 वर्षों में कई बार ईरानी परमाणु कार्यक्रम पर निशाना साधा है, लेकिन हर बार वह या तो अमेरिकी दबाव में या अपनी सैन्य क्षमताओं पर संदेह के कारण अंतिम समय पर पीछे हट गया था। सवाल यह भी है कि इस संघर्ष का इराक, लेबनान, सीरिया और यमन पर क्या असर होगा, क्योंकि वहां पर ईरान एक लंबे समय से अपना प्रभाव जमाए हुए है।

अगर इजराइल अपने प्रयास में विफल हो जाता है। और तमाम चोटें खाने के बावजूद ईरान परमाणु हथियार बनाने में सक्षम हो जाता है, तो इससे क्षेत्र पहले से कहीं अधिक अस्थिर हो जाएगा। तेल संकट भी बढ़ेगा। और संभवतः ईरान अमेरिका-समर्थक अरब शासनों पर हमला करने के लिए प्रेरित हो सकता है। तब अमेरिका के पास इस लड़ाई में कूदने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। ऐसी स्थितियां दुनिया के लिए अधिक घातक होगी, दुनिया में युद्ध के गहराते संकटों से मुक्ति का कोई तो रास्ता निकलना ही चाहिए।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

शिवानन्द मिश्रा
स्तंभकार

चीन का छद्म युद्ध

कलयुग है और इस परिवेश में किसी पर भी पूर्णतया भरोसा करना अपरिपक्वता है, क्योंकि सारा खेल अपने हित से जुड़ा हुआ है। सब अपने हित को साधते हैं।

अमेरिका के संदर्भ में देख लीजिए, राष्ट्रहित में वह किसी को स्थायी मित्र नहीं रखता है। अब इसी चाल में चीन चल रहा है। चीन और रूस को ब्रदरहुड कहा जाता है, किंतु चीन खलीफा बनने की ओर दौड़ रहा है।

बीते दिनों भारत ने पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर किया था, तब चीनी डिफेंस सिस्टम और फाइटर जेट को उड़ा डाला था, जबकि चीनी मिसाइल S-400 और आकाश को भेद नहीं पाए थे। यह वही S-400 प्रणाली है जो रूस से मिली थी, और इसे रणनीतिक दृष्टि से बेहतर ढंग से उपयोग करने के लिए स्वदेशी में अपग्रेड कर लिया। अब चीन, विपक्षी को काम पर लगाकर पूछवा रहे हैं कि भारत के कितने जेट्स गिरे। जबकि चीन अपने सैटेलाइट में इमेज देख सकता है। लेकिन ऐसा कोई सीक्वेंस घटित ही नहीं हुआ, तो भारत की छवि को भ्रम में रखने की चाल चल रहा है।

उधर, रूस की खुफिया एजेंसी FSB (Federal Security Service) ने 9 जून को अपनी आंतरिक रिपोर्ट में खुलासा किया है कि चीन मित्र नहीं अपितु रणनीतिक शत्रु बनने की साजिश रच रहा है, क्योंकि बीजिंग पूर्व रूसी वैज्ञानिकों, सैन्य अधिकारियों और अर्ध-व्यक्तिगत अकादमिक, शैक्षणिक संस्थानों के जरिए जासूसी और तकनीकी सूचनाओं का हस्तांतरण करने की कोशिश कर रहा है।

FSB आगे जोड़ती है कि चीन संवेदनशील सैन्य तकनीकों और रूस में रक्षा-क्षेत्र की गुप्त जानकारियों की खोज के लिए सेवानिवृत्त अधिकारियों से संपर्क कर रहा है अर्थात उन्हें लालची ऑफर देकर तोड़ने की कोशिश कर रहा है ताकि अपने डिफेंस सेक्टर में मजबूती और टिकाऊपन ला सके।

इसके पीछे का आधार भी इसी मिशन सिंदूर से जुड़ा है क्योंकि चीन की पोल भारत ने खोली है। हथियार मार्केट में थू-थू हो रही है, इसलिए वह डैमेज कंट्रोल की प्रक्रिया में है।

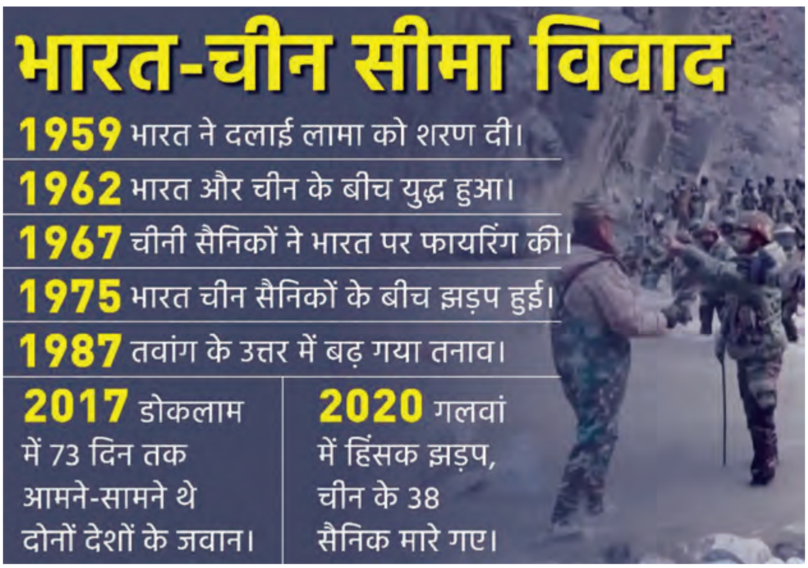

FSB ने चीन को खतरे के रूप में इंगित किया है और सावधान रहने की चेतावनी दी है। दर-असल, ऑपरेशन सिंदूर एक गुप्त सैन्य-साइबर स्ट्राइक थी, जिसमें रूस की पुरानी तकनीक S-400 के जरिए भारत और उसके गुप्त सहयोगियों (संभवतः इजराइल और पूर्वी यूरोप के टैक्टिकल नेटवर्क) ने चीन के एक सामरिक कमांड सेंटर को निष्क्रिय कर दिया।

चीन को इस ऑपरेशन के पीछे रूस की छाया दिखी, इसलिए वह अब रूसी सेवानिवृत्त

अधिकारियों को तोड़कर S-400 जैसी तकनीक का रहस्य जानने की कोशिश कर रहा है।

ऐसा ऐतिहासिक तौर पर पहले भी हो चुका है। सत्तर के दशक में अमेरिका और नाटो देशों ने मिलकर वररफ् जर्मनी आदि के बड़े-बड़े वैज्ञानिकों को किडनैप किया या मार दिया था, ताकि अपने रक्षा क्षेत्र को मजबूत कर सकें।

कई योजनाओं के ब्लूप्रिंट चुरा लिए गए थे, और इजराइल की मोसाद का इस पूरी कार्रवाई में मुख्य रूप से इस्तेमाल किया गया।

अब चीन का लक्ष्य है कि अमेरिका को पछाड़कर वैश्विक डॉन बन जाए। सैन्य सेक्टर में खुली पोल की भरपाई करने की कोशिश में है, जिससे अपने कमजोर पॉइंट्स को छुपाया जा सके और रक्षा बाजार में खोया हुआ विश्वास वापस पाया जा सके।

भविष्य में 'ऑपरेशन सिंदूर' को वर्ल्ड ऑर्डर चेंज में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में पढ़ा और विश्लेषित किया जाएगा। अभी भारत में बहुत से लोगों को अंदाजा नहीं है कि भारतीय सेना ने परदे के पीछे क्या करके दिखाया है। वैश्विक स्तर पर समीकरण बदल रहे हैं। ऐसे ही गुप्त खुलासे आगे भी होते रहेंगे।

पाकिस्तान की दुनिया में किसी देश से प्रतिस्पर्धा नहीं है सिर्फ भारत से है। उसे अमेरिका या चीन की चाटुकारिता करने में कोई शर्म नहीं है। बशर्ते वे भारत के खिलाफ उसकी मदद करते रहें, उसे हथियार देते रहें।

अमेरिका और चीन को भी इतना सस्ता पालतू कहां मिलने वाला है। 1971 में अपने दोनों मालिकों की दोस्ती पाकिस्तान ने ही करवाई थी। फिलहाल चीन और अमेरिका दोनों हाथों से पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। भारत के लक्ष्य दूसरे हैं, उसे अपना खोया हुआ गौरव वापस पाना है। अमेरिका की खोज से पहले दुनिया भारत की ही खोज में लगी रहती थी। दुनिया का हीरों से परिचय ही भारत ने करवाया इसीलिए कलकत्ता बंदरगाह का नाम डायमंडहार्बर है। अमेरिका की तो खोज ही भारत खोजते खोजते अचानक हो गई।

भारत का लक्ष्य दुनिया के प्रथम पंक्ति के देशों में शामिल होना है। पहले दिन से हमारा जोर साइंस टेक्नॉलॉजी, ग्राम विकास, कृषि क्रांति, दुग्ध उत्पादन से लेकर उद्योग व्यापार आधुनिक शिक्षा के मार्ग पर चलते हुए देश को आगे ले जाना है।

पाकिस्तान को अपने मुल्क को सातवीं सदी की रियासते मदीना बनाना है। उनका सेनाध्यक्ष कहता है कि दुनिया में दो ही मुल्क कलमे की बुनियाद पर कायम हुए हैं एक रियासत तैयबा यानी सातवीं सदी का मदीना और दूसरा पाकिस्तान।

बदनसीबी है हमारी कि सदियों से लुटा हुआ हमारा मुल्क अपनी आमदनी का बड़ा हिस्सा अपनी सुरक्षा व्यवस्था में खर्च करने को मजबूर है।

बाहरी परेशानियां अपनी जगह। और घर में भी जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और जातिवाद का छद्म युद्ध की मारा मारी चल रही है। भारत को आगे बढ़ते कौन देखना चाहता है भला? अगर पचीस साल भी भारत को बाहरी और आंतरिक शांति के साथ काम करने का मौका मिल जाए तो भारत अमेरिका और चीन के बराबर आकर खड़ा हो जाएगा।

▸▸ II राजेश कुमार पासी
स्तंभकार

महिलाओं का हिंसक दौर खतरा पैदा कर रहा है

राजा रघुवंशी हत्याकांड में मेघालय पुलिस ने सोनम रघुवंशी और उसके प्रेमी राज कुशवाह का आमना-सामना करवाया। और इसके बाद सोनम रघुवंशी ने यह कबूल कर लिया कि वो अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या में शामिल थी। आजकल यह हत्याकांड पूरे मीडिया में छाया हुआ है। इसे लेकर सोशल मीडिया में यह मुहिम चलाई जा रही है कि शादी के बाद पति के लिए जिंदा रहना बड़ी बात है। हनीमून पर पत्नी के साथ बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप हनीमून से वापिस आ जाएं। अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया में नीले ड्रम का डर फैलाया जा रहा था। और अब उसकी जगह हनीमून ने ले ली है। सोशल मीडिया में नीले ड्रम के हजारों मीम घूम रहे थे। और आज हनीमून के घूम रहे हैं। कई लोगों ने तो पुलिस में शिकायत दे दी कि उनकी पत्नी नीले ड्रम में बंद करने की धमकी दे रही है। राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की शादी के वीडियो वायरल करके बताया जा रहा है कि राजा रघुवंशी शादी में कितना खुश था।

सवाल यह है कि कितनी ही लड़कियां अपनी शादी में बहुत खुश होती हैं। लेकिन ससुराल में जाकर उनको प्रताड़ित होना पड़ता है। पुरुषों का अपनी पत्नी की हत्या करना या उनका उत्पीड़न करना सामान्य घटना है। इन घटनाओं के बाद कभी नहीं कहा जाता कि महिलाएं शादी के बाद जिंदा रहेंगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इन घटनाओं के कारण ही महिलाओं का उत्पीड़न रोकने के लिए कई कानून बनाए गए हैं, जो कि एकतरफा उनका पक्ष लेते हैं। और पुरूषों की सुनवाई नहीं होती। बेशक महिलाओं का अपने पतियों की हत्या करने की घटनाएं कम हों, लेकिन ऐसी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। ये पुरूषों के की जाने वाली घटनाओं से बहुत कम हैं, तो उनकी अनदेखी नहीं की जा सकती। सरकार को इस तरफ ध्यान देना होगा कि जैसे पुरुषों को सजा मिलती है, वैसे ही इन मामलों में महिलाओं को भी सख्त सजा दी जाए।

पहले मेरठ की मुस्कान और अब इंदौर की सोनम के बारे में कहा जा रहा है कि अपने अच्छे भले पतियों को छोड़कर उन्होंने उनसे हर मामले में कमतर प्रेमियों को चुना और उनके लिए अपने पतियों की हत्या कर दी। इसका भी सोशल मीडिया में मजाक बन रहा है कि आजकल लड़कियों के लिए लड़को की शक्ल-सूरत, घर-परिवार और रोजगार महत्वपूर्ण नहीं रह गया है। उनकी पसंद बदल गई है। लोग भूल गए हैं कि आज भी ज्यादातर शादी के मामलों में लड़की की पसंद-नापसंद की अनदेखी की जाती है। इन घटनाओं से यह सीख तो मिलती है कि अब कानूनों को महिलाओं के लिए बनाने की जगह जेंडर न्यूट्रल बनाने की जरूरत है, जो काम पुरुष कर रहा था, अब वो महिलाएं करने लगी हैं। इसलिए अपराधियों को सजा देते समय लिंग के आधार पर भेदभाव बंद होना चाहिए। अब समाज और कानून को इस धारणा से बाहर आने की जरूरत है कि महिला अपराध नहीं कर सकती। जिस तरह पुरुष अवैध संबंधों के लिए अपनी पत्नी की हत्या कर देते हैं, उसी प्रकार महिलाएं भी अपने प्रेम संबंधों के लिए अपने पति को ठिकाने लगा सकती हैं। वैसे देखा जाए, तो ज्यादातर मामलों में परिवार वालों को महिलाओं के प्रेम संबंधों की जानकारी होती है। लेकिन लड़कियों के हितैषी होने का दावा करने वाला परिवार जबरदस्ती उनकी मर्जी के खिलाफ किसी दूसरे लड़के से उसकी शादी कर देता है।

अब कहा जा रहा है कि लड़कियों को अपने पतियों की हत्या करने की जगह तलाक ले लेना चाहिए था। अगर वो उन्हें छोड़ देती, तो कम से कम वो आज जिंदा तो होते। और उनका परिवार उनके साथ खुश होता। सवाल यह है कि जिस परिवार ने एक लड़की की शादी उनकी मर्जी के खिलाफ दूसरी जगह कर दी हो, वो उसे पति को छोड़ने की इजाजत कैसे देगा? अगर किसी लड़की को किसी से प्रेम है, और वो उससे शादी करना चाहती है, तो जबरदस्ती किसी दूसरे लड़के से उसकी शादी करने वाले लड़की के मां-बाप भी लड़के की हत्या के दोषी हैं। क्यों लड़कियां अपने पति की हत्या कर रही हैं, इस पर शोध की जरूरत है। और समाज

को भी समझने की जरूरत है। सिर्फ अपराधियों को सजा देने से बात बनने वाली नहीं है ।

पत्नी का प्रेमी के कारण पति की हत्या करना बेहद भयावह है। और इसके लिए सिर्फ प्रेमी के बहकावे को वजह नहीं मान सकते। कई बार तो पत्नी ही अपने प्रेमी को बहकाकर अपने पति की हत्या करवाती है, ताकि वो उससे स्वतंत्र हो जाए। देखा जाए तो सोनम के मामले में पांच परिवार बर्बाद हो गए हैं। इन परिवारों की बर्बादी के लिए तो सोनम ही जिम्मेदार है, क्योंकि उसके अंधे प्रेम ने यह हत्याकांड करवाया है। क्या हम इन घटनाओं को इक्का-दुक्का होने वाली घटनाएं मान सकते हैं, या ये घटनाएं हमारे सामाजिक पतन का संकेत हैं। रिश्तों में घटता प्रेम और विश्वास एवं बढ़ता लालच और स्वार्थ इन घटनाओं की वजह तो नहीं है। आज हम अपनी मनपसंद जिंदगी जीने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए स्वार्थी होते जा रहे हैं। पुराने रिश्तों के लिए नए रिश्तों की और नए रिश्तों के लिए पुराने रिश्तों की बलि दी जा रही है।

सवाल फिर वही है कि क्या सिर्फ पति-पत्नी के रिश्तों से खून रिस रहा है। और दूसरे रिश्तें इससे अछूते हैं। ऐसा नहीं है, आज अपने ही जान के दुश्मन बन रहे हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था क्या? वास्तव में सदियों से यह चल रहा है। गांवों में जमीन के लिए अपने की अपनों का वर्षों से खून बहाते आ रहे हैं। और सिंहासन के लिए तो यह चलता ही रहा है। देखा जाए तो आज कुछ अलग नहीं हो रहा है। हमारी आदत हो गई है कि हम आज को ज्यादा कोसते हैं, क्योंकि हम आज को जी रहे हैं। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि मानव हमेशा से ऐसा रहा है। यह सिर्फ एक धारणा है कि मानव बदल गया है। और आगे जमाना खराब आ रहा है। अब सोशल मीडिया का जमाना है, तो ऐसी घटनाओं पर पूरे देश में चर्चा होती है। अब खबर सिर्फ एक दिन के लिए नहीं होती, बल्कि कई दिनों और कई बार महीनों तक चर्चा में बनी रहती है। नकारात्मक खबरों के साथ ज्यादातर ये होता है। लेकिन सकारात्मक खबरों की ओर किसी का ध्यान नहीं जाता। इससे समाज पर क्या असर हो रहा है? इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता।

मेरा मानना है कि कुछ घटनाओं के कारण सभी महिलाओं को संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। और उन्हें बदनाम किया जा रहा है। हम मजाक-मजाक में समाज में डर फैला रहे हैं। इतनी महिलाएं हिंसक नहीं हैं, जितनी दिखाई देने लगी हैं। हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि ऐसी घटनाएं बिना लिंग भेद के हो रही हैं। अगर कुछ घटनाओं के कारण मर्द शादी के नाम से डरने लगे हैं, तो एनसीआरबी के आंकड़े देखने के बाद महिलाओं को शादी के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। लेकिन महिलाएं बिना डरे विवाह के मंडप तक जा रही हैं। मेरा मानना है कि इन घटनाओं से सबक लेते हुए हर मां-बाप को अपनी बेटियों की शादी उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर करने से बचना चाहिए। ज्यादातर ऐसी घटनाओं के पीछे अवैध संबंध सामने आ रहे हैं। इस सोच पर विचार करना चाहिए कि लड़की शादी के बाद सब कुछ भुलाकर अपने पति के साथ खुश रहेगी।

ऐसे ही लड़को की भी जबरदस्ती शादी नहीं करनी चाहिए। यह ठीक है कि हर मां-बाप अपने बच्चों का भला सोचते हैं। लेकिन इस चक्कर में किसी दूसरे व्यक्ति की जिंदगी बर्बाद करने से बचना चाहिए। समाज बदल रहा है, क्योंकि इंसान बदल रहा है। और इस बदलाव को समझने की जरूरत है। सभी लोग हालातों से समझौता करके जिंदगी नहीं गुजार सकते हैं। कुछ लोग हालातों को बदलने चल पड़ते हैं। लेकिन गलत तरीके से और फिर वो होता है जो हमें दिखाई दे रहा है। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि हम बेवजह का डर फैला कर विवाह को बदनाम न करें। पहले ही आजकल बच्चे शादी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी घटनाएं उन्हें एक नया बहाना दे सकती हैं।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

प्रियंका सौरभ
वरिष्ठ स्तंभकार

एक पिता की विदाई, और समाज की परीक्षा

लखनऊ के एक रिटायर्ड कर्नल ने अपने बेटों को एक मार्मिक पत्र लिखकर आत्महत्या कर ली। दोनों बेटे अमेरिका में बसे थे। और मां की मृत्यु पर भी पूरी संवेदनशीलता नहीं दिखा सके। पिता ने पत्र में लिखा कि उन्होंने देश को सम्मान दिया। लेकिन समाज को असंवेदनशील पुत्र दे दिए। यह घटना केवल एक आत्महत्या नहीं, बल्कि भारतीय पारिवारिक मूल्यों के पतन का आईना है। आधुनिकता के दौड़ में रिश्तों की संवेदना और बुजुर्गों का सम्मान कहीं पीछे छूटता जा रहा है।

प्रियंका सौरभ

एक फौजी पिता की वर्दी सलामी के लिए नहीं, बल्कि सम्मान और समर्पण के प्रतीक होती है। लेकिन जब वही पिता अपनी अंतिम सांस लेने से पहले अपनी ज़िंदगी के सबसे कड़वे शब्दों में पत्र लिखकर खुद को गोली मार ले, तो यह केवल आत्महत्या नहीं होती – यह एक सामाजिक मृत्यु होती है। लखनऊ की एक पॉश कॉलोनी में रहने वाले रिटायर्ड कर्नल ने ऐसा ही किया। दो बेटे, एक अमेरिका में कॉरपोरेट नौकरी में व्यस्त, दूसरा अपने परिवार के साथ जीवन में लीन। पिता और मां ने पूरी ज़िंदगी इन बेटों की परवरिश में बिता दी थी। ऊंची शिक्षा, बेहतर जीवन, विदेशी स्थायित्व, दुनिया की सुविधाएं – सब दिया, लेकिन आखिर में अकेलेपन का उत्तरदायित्व भी उन्हीं मां-बाप के हिस्से आया।

कहते हैं, हर पिता चाहता है कि बेटा उससे बड़ा बने, लेकिन शायद ही कोई पिता चाहता है कि बेटा उसे भूल जाए। जिस बेटे को कभी बुखार आने पर पिता रातभर सिरहाने बैठा रहा हो, वही बेटा मां की मौत पर कह दे कि 'पापा की मौत में आ जाऊंगा' – तो वहां केवल संबंध नहीं टूटते, आत्मा टूट जाती है। उस पिता ने पत्र में कोई गाली नहीं दी, कोई ताना नहीं दिया, कोई आक्रोश नहीं दिखाया। उन्होंने बस यह कहा कि शायद मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई, क्योंकि मैंने समाज को सभ्य नागरिक नहीं, असंवेदनशील संतति दी।

यह वाक्य जितना सीधा है, उतना ही खौफनाक है। यह एक पिता का नहीं, एक पीढ़ी का दुःख है। यह कहानी किसी एक कर्नल की नहीं है। यह हर उस मां-बाप की है, जो अपने बच्चों को उड़ान देना चाहते हैं, लेकिन बुढ़ापे में लौटती हुई परछाइयां भी नहीं देख पाते। यह उस भारतीय समाज की है, जो अमेरिका जाने वाले बेटे पर गर्व करता है, लेकिन वहीं मां-बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ने पर खामोश हो जाता है। यह उस संवेदनहीनता का बयान है, जो आधुनिकता के मुखौटे के पीछे रिश्तों को घोंट रही है।

पिता की चिट्ठी ने लिखा कि अब उसकी लाश के पास भी कोई इंतजार नहीं करेगा, इसलिए वह खुद ही चला जाता है – ताकि कोई मजबूरी न हो, कोई बहाना न बने, कोई बेटा यूं न कह सके कि 'फ्लाइट नहीं मिली'। यह वाक्य किसी खबर का हिस्सा नहीं, एक सांस्कृतिक हार का एलान है। वह पिता जिसने युद्ध में दुश्मनों से लड़ा, जिसने सेवा में राष्ट्र को प्राथमिकता दी, वह अपने ही घर में अकेलेपन से हार गया। उसकी आखिरी इच्छा थी कि उसके तमगे और तस्वीरें बटालियन को लौटा दी जाएं। शायद वो ये नहीं चाहता था कि उसके बच्चों के ड्राइंग रूम में झूठी स्मृति के रूप में उसकी तस्वीर टंगी रहे।

हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं, जहां हर त्योहार पर 'परिवार के साथ समय बिताएं' जैसे विज्ञापन चलाए जाते हैं, लेकिन असल में माता-पिता के पास समय बिताने वाला कोई नहीं होता। वीडियो कॉल पर रिश्ता निभाया जाता है, जन्मदिन पर केक भेजकर ज़िम्मेदारी पूरी मानी जाती है, और अंत्येष्टि में आना 'काम की व्यस्तता' के आधार पर टाला जा सकता है। कर्नल साहब के बेटे के लिए यह सिर्फ 'एक और दिन' रहा होगा। लेकिन उस दिन ने एक पिता को चुपचाप शहीद कर दिया – इस बार बिना दुश्मन के, बिना युद्ध के, बिना आदेश के।

जिस समाज में माताएं बेटे को यह सिखाती थीं कि बुढ़ापे में मां-बाप भगवान होते हैं, उस समाज में बेटे मां के निधन पर आने से कतराने लगे हैं। यह संस्कारों की नहीं, अवसरवादिता की पीढ़ी है।

जहां 'हमारी प्राथमिकताएं बदल गई हैं' जैसे वाक्य, रिश्तों की कब्र पर पत्थर बनकर रख दिए गए हैं। रिश्ते अब भावना से नहीं, सहूलियत से निभाए जाते हैं। कोई फोन करेगा तो बात होगी। कोई कहेगा तो आऊंगा। कोई मरेगा तो सोचूंगा। यही हमारी आधुनिक संस्कृति है, जो रिटायरमेंट के बाद मां-बाप को केवल एक खर्च या बोझ समझती है।

क्या हम सोचते हैं कि हमारे बच्चों को हम जैसा ही व्यवहार मिलेगा? क्या जो आज बोया जा रहा है, वही कल काटा नहीं जाएगा? बेटों ने क्या सिर्फ इसलिए पढ़ाई की थी कि वे संवेदना से चूक जाएं? अगर शिक्षा केवल कैरियर और डॉलर कमाने तक सीमित रह जाए, तो वह एक आदर्श संतान नहीं, एक संवेदनहीन मशीन तैयार करती है।

कर्नल साहब ने खुद को गोली नहीं मारी – उन्होंने एक घोषणा की थी। कि वह एक असफल पिता थे, क्योंकि उन्होंने ऐसे बेटे पैदा किए, जो शव देखने से डरते थे, लेकिन सेल्फी लेने में नहीं झिझकते। उन्होंने एक ऐसा समाज छोड़ा, जो बुजुर्गों की बातें 'बोरिंग' समझता है और बूढ़ों के आंसू सिर्फ 'ग्लानि' का विषय बनते हैं, करुणा का नहीं।

अब सवाल यह है कि हम इस पत्र को पढ़कर केवल अफसोस जताएं या आत्मपरीक्षण करें। हम क्या वाकई उस दिशा में जा रहे हैं, जहां रिश्तों का मूल्य डॉलर से कम है? क्या हम अपने बच्चों को यह शिक्षा दे रहे हैं कि सफलता का मतलब पीछे मुड़कर न देखना है? कर्नल साहब का पत्र चेतावनी है – उन सब के लिए जो सोचते हैं कि विदेश में बस जाने से जड़ें खत्म हो जाती हैं। नहीं, जड़ें हमेशा रहती हैं। सूखती हैं, तबाही लाती हैं।

यह समाज तब तक जीवित रहेगा, जब तक बुजुर्गों को सम्मान मिलेगा। जिस दिन मां की चिता को बेटे 'इवेंट' मानने लगेंगे, उस दिन से सभ्यता खत्म होनी शुरू हो जाएगी। आज जो कर्नल साहब के साथ हुआ, वह कल किसी और के साथ होगा। शायद आपके साथ। शायद मेरे साथ।

आखिर में बस इतना कहना चाहूंगी – रिश्ते निभाइए। मां-बाप को समय दीजिए। अमेरिका जाकर सफलता अर्जित करना बुरा नहीं, पर उस उड़ान में अगर संवेदनाएं पीछे छूट जाएं तो वह उड़ान नहीं, विस्मृति बन जाती है।

कर्नल साहब की आत्महत्या, एक पिता का मर जाना नहीं है – यह हमारे समाज की आत्मा की पराजय है। और अगर अब भी हम नहीं चेते, तो अगली पीढ़ी हमें केवल बर्थडे कार्ड और अंत्येष्टि के टोल फ्री नंबर ही देगी।

ग्लोबल ऑब्ज़र्वर पढ़ें और दोस्तों को पढ़ाएं–एक शुभचिंतक

समाजसेवी महेन्द्र यादव एडवोकोट को शेर ए दिल्ली चौधरी ब्रह्म प्रकाश यादव शिखर सम्मान

II सैयद असद आज़ाद
लेखक, 'मेघ देवता'

सेवा मनुष्य के जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। सेवा-भाव से पल्लवित, पुष्पित व्यक्ति ही सफल है। दुनिया का जीवन चक्र कई दौरों से गुज़रता रहा है। त्रासदी ने हर दौर में अपनी सीमा लांघते हुए अंतहीन यात्रा की है। लेकिन इस त्रासदी पर विजय पाने वाली जिजीविषा एवं मानसिकता ने उसे परास्त भी की है।

समाज भीतरी और बाहरी आवरणों से परिष्कृत होता है। सबकुछ मनुष्य की भावना पर निर्भर करता है। भावना स्वच्छ हो, तो पूरा का पूरा वातावरण ही स्वच्छ हो जाता है। सेवा भावना आज दिखावा और हक़ीक़त भी है। लेकिन समाज सेवा का रूप और स्वरूप बदलते समय के साथ बदलते हुए मोहक और मनमोहक भी हुआ है। विभिन्न प्रकार के सामाजिक अवरोध और विकास में बाधा उत्पन्न करने वाली त्रासदी के समय, यही सेवा भावना ने हमें एक दूसरे के लिए कारगर और उपयोगी साबित किया है।

प्राकृतित आपदा तो इस संसार का एक हिस्सा बन चुका है। कहीं भूकंप की त्रासदी मानव को झकझोर रही है, तो कहीं सुनामी अपने वीभत्स रुप को सामने लाकर पूरी की पूरी सभ्यता को लील जाने को आतुर भी दिखती है। बाढ़, सूखा, तूफां और बारिश से तो भारत सदियों से आहत रहा है। लेकिन इस विराट आपदा को भी 'साथी हाथ बढ़ाना' की तर्ज पर हर बार पटरी पर लाया जाता रहा है।

दुनिया में ऐसे कई लोग हैं, जो समाज सेवा के क्षेत्र में निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं। उनके प्रयासों से समाज में सकारात्मक

बदलाव आते रहे हैं। और देखते-देखते एक बेहतर भविष्य का निर्माण हुआ है। यही भावना कई बार हमें एक दूसरे को देखकर सीखने की ललक पैदा करती है। याद कीजिए 1964 के साल को। राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन ने इसी साल ग़रीबी के ख़िलाफ़ युद्ध की घोषणा की थी। और इस तरह से लोगों के निस्वार्थ भाव से सेवा करने की मंशा में तीव्रता आई। और एक दूसरे से प्रेरणा लेकर लोगों ने ग़रीबों के प्रति हमदर्दी रखते हुए मदद करने की अपनी नीति को अमली जामा पहनाया।

दरअसल निस्वार्थ भाव से समाज सेवा मनुष्य का जन्मजात कर्तव्य है। महात्मा गांधी, डॉ. भीमराव अंबेडकर, विनोबा भावे, मदर टेरेसा, और बाबा आम्टे जैसे नाम इसके लिए उपयुक्त साबित हुए हैं। समाज के लिए इन सभी का कल्याणकारी योगदान सफल रहा है। आज भी देश और दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं, जिन्होंने समाज सेवा के लिए अपने को समर्पित कर दिया है। ऐसे ही एक नाम की चर्चा मैं यहां कर रहा हूं। यह नाम महेन्द्र यादव एडवोकेट का है। इनके अंदर यौवन से ही ग़रीबों और बेसहारों लोगों के लिए एक दर्द, एक टीस रही है। और वजह रही कि उन्होंने जमकर ऐसे लोगों की मदद की। ग़रीबों की हर तरह से मदद करना। और सामाजिक नाइंसाफ़ी को रोकने में उनकी सहायता करना, भी इनके स्वभाव की एक महत्वूर्ण कड़ी मानी जाती है। आज भी इनका सामाजिक सेवा का दायित्व कम नहीं हुआ है। वे निरंतर अपनी सोच और सामर्थ्य के हिसाब से लोगों की मदद करते रहते हैं। इन दिनों हर महीने 1500 से लेकर 2000 लोगों को भोजन कराना, इनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है।

इनकी भलमनसाहत, उदार ह्दय, समाज कल्याण का विराट रूप और स्वरूप के मद्देनज़र ‘दूसरा मत’ ने इन्हें शेर ए दिल्ली चौधरी ब्रह्म प्रकाश यादव शिखर सम्मान प्रदान किया है। उन्हें दिल्ली में उनके आवास भर शॉल, प्रशस्ति-पत्र, शील्ड एवं मां : एक गजल व तस्वीर पुस्तक भेंट कर सम्मानित किया गया।

एयर इंडिया जो सरकारी जड़ता से निकली और कॉर्पोरेट ब्यूरोक्रेसी में फंसी?

एस. ए. तिवारी
वरिष्ठ पत्रकार

जनवरी 2022 में जब टाटा समूह ने एयर इंडिया का अधिग्रहण किया, तब पूरे देश में एक नई उम्मीद जगी थी। माना जा रहा था कि वर्षों से सरकारी उदासीनता, निर्णयात्मक सुस्ती और लालफीताशाही में फंसी एयर इंडिया अब एक वैश्विक मानकों की एयरलाइन बनेगी। लोगों को विश्वास था कि टाटा के नेतृत्व में यह एयरलाइन तकनीक, सेवा, सुरक्षा और प्रतिस्पर्धा के नए आयाम गढ़ेगी लेकिन तीन वर्षों के भीतर एयर इंडिया जिस राह पर बढ़ी है, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह एयरलाइन एक कॉर्पोरेट र-ीस्ट्रक्चरिंग लैब में बदल गई है जहां हवाई जहाज, यात्री अनुभव और सुरक्षा प्राथमिक नहीं बल्कि ऑफिस स्थानांतरण, वीआरएस, पदों की अदला-बदली और कॉर्पोरेट ढांचे की बातें मुख्य हो गई हैं।

टाटा समूह से टेकओवर के बाद यह अपेक्षा थी कि एयर इंडिया सबसे पहले अपने पुराने विमानों की मरम्मत, नए विमानों की खरीद और यात्रियों को बेहतर अनुभव देने पर ध्यान देगी लेकिन अधिकतर सुर्खियां इस बात की बनीं कि कैसे एयर इंडिया अपने मुंबई, कोचीन और बैंगलोर जैसे पुराने परिचालन केंद्रों को बंद कर रहा है, कैसे वीआरएस देकर पुराने कर्मचारियों को हटाया जा रहा है और कैसे सभी कर्मचारियों को जबरन गुरुग्राम शिफ्ट करने के फरमान सुनाए जा रहे हैं। एयर एशिया का बैंगलोर ऑफिस, विस्तारा का मर्जर, एयर इंडिया सेट्स का मुंबई से दिल्ली स्थानांतरण—सब कुछ एक ही दिशा में बढ़ाः सब कुछ गुरुग्राम में समेटो। इस बदलाव का सबसे बड़ा नुकसान हुआ एयर इंडिया के पुराने कर्मचारियों और ऑपरेशनल नेटवर्क को जो वर्षों से इन शहरों में जमे हुए थे और एयरलाइन की कार्य संस्कृति का हिस्सा बने हुए थे। जबरिया स्थानांतरण और ऑफिस बंद करने जैसे फैसले शायद कॉर्पोरेट दृष्टि से सही लग सकते हैं लेकिन यह एयरलाइन कर्मचारियों के मनोबल और संचालन में असंतुलन का बड़ा कारण बन गए।

टाटा समूह ने एयर इंडिया में जो नई टीम बनाई, उसमें शीर्ष चार में से सिर्फ सीईओ विल्सन कैंपबेल ही एविएशन बैकग्राउंड से हैं। बाकी तीनों सीसीओ निपुण अग्रवाल, सीएफओ संजय शर्मा और सीएचआरओ रवींद्र कुमार जीपी—ऐसे लोग हैं जिनका एविएशन से कोई अनुभव नहीं रहा। निपुण अग्रवाल, जिन पर एयरलाइन की खरीद, मरम्मत, और उत्पाद विकास जैसी रणनीतिक जिम्मेदारियां हैं, वे एयर इंडिया से पहले कभी भी एविएशन सेक्टर का हिस्सा नहीं रहे। उनका पूरा अनुभव टाटा समूह में कॉर्पोरेट फाइनेंस स्ट्रैटेजी में रहा है। सवाल यह उठता है कि क्या ऐसे अधिकारी एविएशन की बारीकियों, विमान रखरखाव, इमरजेंसी निर्णय, या स्पेयर पार्ट्स की क्रिटिकलिटी को पूरी तरह समझ सकते हैं?

एविएशन का खर्च, एमआरओ इंश्योरेंस, और एएमसी जैसे मुद्दे एक सामान्य कॉर्पोरेट खरीद प्रणाली से बहुत अलग होते हैं। एयरक्राफ्ट की सुरक्षा और परिचालन में देरी का कोई स्थान नहीं होता। इसी प्रकार सीएफओ संजय शर्मा की नियुक्ति भी सवालों में है। उनके पूर्ववर्ती विनोद हेजमाड़ी के पास तीन दशक का एविएशन अनुभव था लेकिन संजय शर्मा टाटा प्रोजेक्ट्स से आये हैं, जहां उनका अनुभव मुख्य रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोजेक्ट फाइनेंस में रहा है। एविएशन सेक्टर की लागत और ऑपरेशनल इमरजेंसी का वे अनुभव नहीं रखते। तीसरी महत्वपूर्ण नियुक्ति रवींद्र कुमार जीपी की रही जिनका पूर्व का अनुभव टाटा मोटर्स में रहा है। एयरलाइन में पायलट्स, केबिन क्रू, एयर ट्रैफिक स्टाफ की कार्य परिस्थितियां बेहद संवेदनशील होती हैं। यह कारखानों या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे नहीं होते। एयरलाइन में एचआर की छोटी सी चूक भी गंभीर हादसे का कारण बन सकती है। एविएशन में एक्सेल शीट से आगे देखना जरूरी टाटा समूह का यह कॉर्पोरेट अप्रोच एयर इंडिया में बहुत गहराई तक दिखता है। फैसले शायद एक्सेल शीट पर कॉस्ट कटिंग को ध्यान में रखकर लिए जा रहे हैं लेकिन एयरलाइन इंडस्ट्री केवल आंकड़ों पर नहीं चलती। यहां सेकंड्स का महत्व होता है, सुरक्षा सर्वोपरि होती है और निर्णय क्षमता का आधार फील्ड एक्सपीरियंस होता है।

मुंबई, कोचीन, बैंगलोर जैसे पुराने एयरलाइन हब्स से स्टाफ को जबरन हटाना, पुराने ऑफिस बंद करना, कर्मचारियों को मजबूरन गुरुग्राम लाना यह सब कॉर्पोरेट निर्णय तो हो सकते हैं लेकिन क्या यह एयरलाइन के संचालन और सुरक्षा के लिए उचित है? इस प्रश्न का उत्तर समय मांगेगा। टाटा समूह जैसा विशाल, अनुभवी और प्रतिष्ठित कॉर्पोरेट हाउस कैसे इतनी बुनियादी गलती कर गया? एयरलाइन ऑपरेशन के तीन प्रमुख स्तंभ—खर्च प्रबंधन, खरीद-रखरखाव और मानव संसाधन—तीनों ही ऐसे लोगों के हाथ में सौंप दिए गए जिनके पास एविएशन का कोई पूर्व अनुभव नहीं था। क्या टाटा समूह ने एयर इंडिया के मेकओवर को केवल कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में सीमित कर दिया? क्या वो एविएशन सेक्टर की जमीनी जरूरतों, तकनीकी बारीकियों और ऑपरेशनल संवेदनशीलता को नजरअंदाज कर गए?

टाटा समूह को समझना होगा कि एयरलाइन चलाना किसी कार फैक्टरी या इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से भिन्न है। यहां मानवीय समझ, तत्काल निर्णय क्षमता और एविएशन-विशेषज्ञता सर्वोपरि होती है। अगर एयर इंडिया को केवल कॉर्पोरेट केपीआई के मापदंड पर चलाने की कोशिश जारी रही तो यह एक 'ब्रांडेड ढांचा' बनकर रह जाएगी जिसकी पहचान केवल कॉर्पोरेट ब्यूरोक्रेसी बन जाएगी न कि एक भरोसेमंद राष्ट्रीय एयरलाइन। सरकार को भी इस पर ध्यान देना होगा। उसे यह जांच करनी चाहिए कि क्या निजीकरण के बाद एयर इंडिया में सुरक्षा के ऊपर कॉस्ट कटिंग और लाभ को प्राथमिकता तो नहीं दी जा रही! क्या टॉप मैनेजमेंट का गैर-एविएशन अनुभव किसी अनदेखे खतरे को जन्म दे रहा है? क्या दुर्घटनाग्रस्त विमान के इंजन की मरम्मत और ऑपरेशनल फैसले में कोई चूक हुई? यह समय है कि टाटा समूह एविएशन-विशेषज्ञ नेतृत्व को प्राथमिकता दे, ऑपरेशनल निर्णयों को कॉर्पोरेट मीटिंग रूम से निकालकर ग्राउंड लेवल पर ले जाए और कर्मचारियों के साथ अधिक मानवीय दृष्टिकोण अपनाए। यदि ऐसा किया गया, तो एयर इंडिया ना केवल एक मजबूत ब्रांड बन सकती है बल्कि एक सुरक्षित, भरोसेमंद और गर्व का प्रतीक भी। अभी भी समय है. अगर टाटा ग्रुप अपनी रणनीति में यह बदलाव कर ले तो भविष्य की कई जिंदगियां सुरक्षित हो सकती हैं।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं। ये लेखक के अपने विचार हैं।)

डॉ. रमेश ठाकुर
स्तंभकार

विमान दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति आखिर कब तक?

अहमदाबाद विमान हादसे को हफ्ते भर होने को है। घटना के कारणों को जानने के लिए सवालों की बौछारें जारी हैं। तीन महीने बाद अंतिम जांच रिपोर्ट आएगी। सवाल ये है इतनी लंबी अवधि क्यों? क्या ये सब उठते शोर को कम करने की कोशिश तो नहीं? हवाई यात्राएं कब तक असुरक्षित रहेंगी। इसका जवाब प्रत्येक घटना के बाद जिम्मेदार व्यक्तियों से पूछा जाता है लेकिन दुर्भाग्य देखिए हर कोई बचता है। इतना तय है इस विमान घटना की अगर निष्पक्ष जांच-पड़ताल नहीं हुई तो अकाल मरे सैकड़ों लोगों की मृत्यु आत्माएं दर-दर भटकती रहेंगी। शासन से लेकर सिस्टम तक सभी अनुत्तरदायी बने हुए हैं। एयरलाइंस निजी हैं, एयरपोर्ट, कर्मचारी व अन्य विमानन व्यवस्थाएं तक निजी हैं, तो आखिर उत्तरदायी होगा कौन? वर्ष 2025 के गुजरे 6 महीनें, 6 बड़े हादसों के नाम रहे। महाकुंभ में भगदड़ से शुरू हुआ दर्दभरा सिलसिला बेंगलुरू भगदड़ से होता हुआ दिल्ली, मुंबई के बाद अहमदाबाद प्लेन हादसे तक जा पहुंचा है। पर, मौजूदा विमान हादसा तमाम सस्पेंस, बोइंग की लापरवाही, सुस्त सिस्टम की उदासीनता की ओर इशारा करता है।

हादसे पर शक तब और गहरा गया, जब जिंदा बचे यात्री ने प्लेन क्रैश से पहले ही जमीन पर गिरना बताया। यहीं से साजिश की बड़ी बू आने लगी है। हैरान करने वाली बात है कि ऐसा कैसे संभव है। यात्री प्लेन में था, किसी बस या रेलगाड़ी में नहीं था जिससे कोई खिड़की तोड़कर कूद जाएगा। जांए एजेंसियों ने यात्री के बयान के बाद से अपनी जांच का एंगल दूसरी ओर घुमा दिया है। कहीं कोई बड़ी साजिश तो नहीं, बिस्फोट से तो नहीं उठाने की कोशिश हुई? दरअसल, भारत में विमानों की तकनीकी सुरक्षा, उड़ान निरीक्षण और संकटकाल में जवाबदेही एक ऐसे संस्थागत सिस्टम के सिर है जिसपर सत्ता की सौदेबाजी और भ्रष्टाचार ने खोखला किया हुआ है । तत्कालीन उड़यन मंत्री प्रफुल्ल पटेल पर लगे आरोपों ने विमानन के भीतर सच्चाई को भी पब्लिक कर दिया था।

सबसे बड़ा सवाल यही है कि दुनिया के टॉप-5 देशों में शुमार इंडियन एविएशन सेक्टर होने के बावजूद अविश्वसनीय क्यों है? लगातार होते हादसे यात्रियों के भरोसे तोड़ रहे हैं। डीजीसीए अपने को स्वतंत्र करे, अनुत्तरदायी, पक्षकारी और सत्ता के दबाव से बाहर निकले। विमान हादसे कब तक होते रहेंगे? क्या कभी रूक पाएंगे भी या नहीं? विमान क्षेत्र को अपडेट करने की जरूरत बहुत पहले से है, आधुनिक तकनीकों को अपनाना होगा लेकिन हमारे यहां एक हादसा होता है, उस पर शोर मचता है और कुछ दिनों बाद शांत हो जाता है, फिर नए हादसे का इंतजार होने लगता है। अहमदाबाद विमान दुर्घटनाग्रस्त से पूर्व में भी कई दर्दनाक हवाई हादसे देश में हुए पर, उनसे सबक नहीं सीखा गया? जिसका नतीजा ये है कि फिर से एक हादसे के रूप में पुनरावृत्ति हो गई।

वर्ष 2024-25 के बजट में केंद्र सरकार ने विमान और एयरो इंजन के लिए 48,614 करोड़ रूपए आवंटन किया हुआ, बावजूद इसके हवाई यात्राए अमंगल साबित हो रही हैं। देश की तकरीबन एयरलाइंस निजी हैं और मौजूदा समय में नब्बे से ज्यादा एयरपोर्ट लीज पर कंपनियों के हाथों में हैं जो इस तंत्र को अपने मनमाने ढंग से संचालित करती हैं। इसलिए कह सकते हैं विमान तंत्र अब रामभरोसे ही हैं। अहमदाबाद विमान घटना की 6 जांच एजेंसियां पड़ताल में लगी हैं। हादसे के शुरूआती कारण जो निकले हैं उनमें सीधे-सीधे मानवीय हिमाकतें दिखाई पड़ती हैं। विमान मात्र 625 फीट उंचाई से क्रैश हुआ। उड़ने के मात्र 84 सैंकड में ही पायलट औार एटीएस के बीच का संपर्क टूट गया। प्लेन रनवे नंबर-23 से उड़ा जिससे उड़ाने कई सप्ताह से रोकी हुईं थीं, उससे उडान भरने की इजाजत क्यों दी गई? एटीएस का जवाब है कि उन्होंने पायलटों से संपर्क किया, कॉल भी की लेकिन जवाब नहीं मिला? जबकि, पायलटों ने एटीएस से तत्कालीन 'मेयडे इमरजेंसी' कॉल की थी हालांकि इसकी सच्चाई ब्लैक बॉक्स के खुलने के बाद ही पता चल पाएगा जो मिल चुका है।

हादसे के तत्कालीन कारण सीधे एयरपोर्ट अथॉरिटी, विमानन कंपनियों और उडयन विभाग पर खड़े करते हैं। कुछ वर्ष पूर्व केंद्र सरकार ने देशभर के एयरपोर्ट की सुरक्षा-समीक्षा की थीं। रिपोर्ट में सामने आया था कि कई ऐसे रनवे हैं जो बोईंग विमानों का भार झेलने के लायक नहीं हैं। अहमदाबाद विमान हादसे की जिम्मेदारी स्थानीय अथॉरिटी, प्रशासन और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सिर जानी चाहिए। जिम्मेदार टॉप अधिकारियों पर केस दर्ज हो, हादसे में हताहत बेकसूर हवाई यात्रियों की हत्या का मुकदमा होना चाहिए। मृतकों में मुआवजा राशि बांट कर घोर लापरवाही और मुंह खोले खड़ी कमियों पर पर्दा नहीं डाला जाए। देश के हवाईअड्डों की स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है। महज दिल्ली, मुंबई जैसे दो-तीन ही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के एयरपोर्ट हैं जबकि, देश में एविएशन सेक्टर में भारी संभावनाएं हैं। यह क्षेत्र सालाना 14 फीसदी की दर से ग्रोथ कर रहा है। हवाई यात्रियों में भारी इजाफा होने के बाद भी अभी तक टियर दो और टियर तीन श्रेणी के शहरों को हवाई रूटों से नहीं जोड़ा गया. घटना के संभावित पहलुओं को चिंहित किया जाए और जिम्मेदारी तय हो?

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

विजय गर्ग
स्तंभकार

उच्च शिक्षा का पिछड़ता स्तर

देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था उदारीकरण के बाद आगे तो बढ़ी, लेकिन उसी गति से उसमें गुणवत्ता विकसित नहीं हो पाई। उदारीकरण के तीन दशक पूरे हो चुके हैं, मगर इसका लाभ उच्च शिक्षा में केवल कमाई के अवसर के रूप में देखा गया। खास यह भी है कि तकनीकी शिक्षा के लिए आल इंडिया काउंसिल आफ टेक्निकल एजुकेशन (एआइसीटीई) को मानक तय करने के लिए 1987 में बनाया गया था। इसके नियमों की खूब अवहेलना हुई। समय के साथ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) भी नकेल कसने में कम ही ।कम ही कामयाब रहा। आकर्षक विज्ञापनों और चमचमाते सपनों के साथ साथ युवाओं के हाथ में उच्च शिक्षण संस्थाओं ने डिग्रियां तो खूब थमाईं, पर कौशल के मामले में वे खोखले ही ।रह गए। यूजीसी की वेबसाइट को खंगालें, तो मौजूदा समय में सभी प्रारूपों में 1200 से अधिक विश्वविद्यालय हैं, जिनमें 57 केंद्रीय और 502 राज्य विश्वविद्यालय हैं। सभी उच्च शिक्षण संस्थान और इनसे जुड़े कालेज हर साल तकरीबन चार करोड़ से अधिक युवाओं की तकदीर बनाते हैं। ऐसे संस्थान स्थापित करने के लिए बहुत बड़ी राशि की आवश्यकता पड़ती है। निराशा की बात यह है कि इनमें कई संस्थान शिक्षा को धन उगाही का जरिया बना लेते हैं और डिग्रियां बांटना एक तरह से कारोबार बन जाता है।

असल में शिक्षा कोई रातों-रात विकसित होने वाली व्यवस्था नहीं है। वैश्वीकरण के बाद उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कई दरवाजे खुले मगर व्यावहारिक तौर पर अब ये विफल दिखाई देते हैं। भारत

में विगत तीन दशकों शिक्षा संस्थानों के प्रति काफी नरमी बरती जा रही है और शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट की मुख्य वजह भी यही है भारत सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। संसार की सबसे बड़ी युवा आबादी यहीं है। जिस गति से शिक्षा लेने वालों की संख्या यहां बढ़ी, शिक्षण संस्थाएं उससे तालमेल नहीं बैठा पाईं। कुछ क्षेत्रों में बिना किसी त के कमाने वाली शिक्षण संस्थाओं की बाढ़ आ गई। इंजीनियरिंग कालेज इसी तर्ज पर पर विकसित हुए और यह बात तब और पुख्ता हो जाती है, जब आंकड़े बताते हैं कि देश देश में इंजीनियरिंग की सफलता दर आम तौर पर दस फीसद से अधिक नहीं होती है जबकि हर साल 15 लाख इंजीनियरिंग स्नातक कालेजों से निकलते हैं। इतना ही नहीं 40 फीसद आइआइटी स्नातक भी नौकरी पाने में असफल रहे 'इंडियाज ग्रेजुएट स्किल्स इंडेक्स' के अनुसार, देश देश में वर्ष 2024 में लगभग 57 फीसद स्नातकों के पास आवश्यक कौशल नहीं है।

सवाल उठता है कि शैक्षणिक वातावरण हमारे यहां कैसा है। अब शिक्षण संस्थानों को सुशासन के मार्ग की ओर ले जाने की जरूरत है। उच्च शिक्षा को लेकर दो प्रश्न उभरते हैं। पहला यह कि क्या विश्व परिदृश्य में तेजी से बदलते घटनाक्रम के बीच उच्चतर शिक्षा, शोध और ज्ञान के विभिन्न संस्थान स्थिति के अनुसार बदल रहे हैं? दूसरा क्या अर्थव्यवस्था, दक्षता और प्रतिस्पर्धा के प्रभाव में शिक्षा को तकनीक से जोड़ने का कोई बड़ा लाभ मिल रहा है यदि हां, तो सवाल यह भी है कि क्या परंपरागत मूल्यों और उद्देश्यों का संतुलन इसमें बरकरार है? विभिन्न विश्वविद्यालयों में शुरू में ज्ञान के सृजन का हस्तांतरण भूमंडलीय हिस्सेदारी के आधार पर हुआ था। धीरे-धीरे बाजारवाद के कारण शिक्षा गुणवत्ता के मामले में पिछड़ती गई। वर्तमान में तो इसे बाजारवाद और व्यक्तिवाद के संदर्भ में परखा और जांचा जा रहा है। तमाम ऐसे कारकों के चलते उच्च शिक्षा सवालों में घिरती चली गई। देश में उच्च शिक्षा की स्थिति चिंताजनक क्यों हुई, इसे समझना होगा। ऐसा इसलिए हुआ कि इस क्षेत्र में उन मानकों को कहीं अधिक ढीला छोड़ दिया गया, जिसे लेकर एक निश्चित नियोजन होना चाहिए था। उच्च शिक्षा में गुणवत्ता तभी आती है, जब इसे शोधपरक बनाने का प्रयास किया जाता है न कि रोजगार जुटाने मात्र का जरिया बनाया जाता है। निजी विश्वविद्यालय फीस वसूलने में पूरा दम लगाए रखते हैं, पर उच्च शिक्षा के प्रति इनकी प्रतिबद्धता कम ही दिखती है। कोई दो मत नहीं कि यहां शिक्षा एक व्यवसाय है, इसका अपना एक आकर्षण है। ऐसा लगता है कि अब तो आनलाइन व्यवस्था में शिक्षण संस्थान मोबाइल और लैपटाप में सिमट चुके हैं। पाइल आ तीन नवंबर 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय में विश्वविद्यालयों के दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रमों पर सवाल उठाया था। शीर्ष अदालत ने उ-ड़ीसा हाईकोर्ट के इस फैसले को कि पत्राचार के जरिए तकनीकी शिक्षा सही है, उसे खारिज करते हुए स्पष्ट कर दिया था कि किसी भी प्रकार की तकनीकी शिक्षा दूरस्थ पाठ्यक्रमों के माध्यम से उपलब्ध नहीं कराई जा सकती। शीर्ष अदालत के इस फैसले से मे-डिकल, इंजीनियरिंग और फामेर्सी समेत कई अन्य पाठ्यक्रम जो तकनीकी पाठ्यक्रम की श्रेणी में आते हैं, उन्हें लेकर विश्वविद्यालय अब मनमानी नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, इस फैसले से पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के उस उस निर्णय को भी समर्थन मिलता है जिसमें कंप्यटर विज्ञान में में पत्राचार के माध्यम से ली गई डिग्री को नियमित तरीके से हासिल डिग्री की तरह मानने से इनकार कर दिया गया था। कचोटने वाली बात यह भी है कि उच्च शिक्षा के नाम पर चौतरफ अव्यवस्था फैली हुई है। बीते दो दशक में दूरस्थ शिक्षा को लेकर गली-मोहल्लों में दुकानें खुलने का सिलसिला आज भी जारी है।

उत्तर प्रदेश के कई नामी-गिरामी विश्वविद्यालय भी इस मोह से नहीं पाए। स्नातक और परास्नातक समेत कई व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को लेकर दूरस्थ माध्यम से बिना किसी खास कसौटी के न केवल केंद्र खोलने की अनुमति दी गई, बल्कि स्वयं के साथ इससे जुड़े ठेकेदारों को भी फायदा पहुंचाने लगे। इतना ही नहीं, बीटेक से लेकर एमबीए तक की डिग्रियां भी दूरस्थ माध्यम से ऐसे से ऐसे केंद्रों से सहज रूप से उपलब्ध होने लगी।

दरअसल, शिक्षण संस्थाओं ने व्यवसाय अधिक किया, जबकि नैतिक धर्म का पालन करने में कोताही बरती है। हमारे छह पुराने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आमतौर पर राष्ट्रीय रैंकिंग में सबसे आगे रहते हैं, उन्होंने मूल्यांकन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर चिंताओं का हवाला देते हुए लगातार पांचवें वर्ष ‘टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग’ का बहिष्कार जारी रखा है। वैश्विक स्तर पर, आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय लगातार नौवें वर्ष शीर्ष स्थान पर बना हुआ है, जबकि एमआइटी स्टैनफोर्ड को पछाड़ कर दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। ऐसे में हमारी शिक्षा व्यवस्था किस मुकाम पर है? जाहिर है जब तक उच्च शिक्षण संस्थान चलाने वाले गंभीर नहीं होंगे, शिक्षा के महत्त्व को नहीं समझेंगे और शोध के मामले में गंभीर नहीं होंगे, तब तक यह व्यवस्था हांफती रहेगी और इसमें स-ुशासन की दरकार बनी रहेगी।

(ये लेखक के अपने विचार हैं। लेखक सेवानिवृत्त प्रिंसिपल हैं)

विधानसभा चुनाव के लिए बेगूसराय कांग्रेस ने कसी कमर

बेगूसराय, मटिहानी और बछवारा सीट पर पेश की जोरदार दावेदारी

एस आर आज़मी

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन का एक महत्वपूर्ण घटक दल कांग्रेस पार्टी ने भी कमर कस ली है। नए साल जनवरी से लेकर जून तक पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चार बार बिहार का दौरा किया। और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित दर्जनों वरिष्ठ नेताओं का विभिन्न क्षेत्रों में आना जारी रहा।

सात विधानसभा क्षेत्र वाले बेगूसराय जिला में भी राहुल गांधी की पद यात्रा हुई। जिला कांग्रेस भवन में पार्टी की आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा, सोलापुर की सांसद परिणीति शिंदे, पार्टी के प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरू सहित दर्जनों प्रांतीय नेताओं की भागीदारी रही। इस दौरान पार्टी एवं जिला के वरिष्ठ नेताओं ने जिले की चार सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार दिए जाने की वकालत की। कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र में पार्टी संगठन की मजबूती और रुझान को दर्शाते हुए बेगूसराय, मटिहानी, बछवारा और तेघरा विधानसभा जैसे सीटों की मांग की।

बेगूसराय विधानसभा सीट पर ग़ौर करने पर सबसे ऊपर श्रीमती अमिता भूषण का नाम सामने आता है। वे यहां से एक टर्म विधायक रह चुकी हैं। और दूसरे टर्म में मामूली वोट के अंतर से पराजित हो गईं। मालूम हो कि श्रीमती अमिता भूषण ने 2009 में कांग्रेस से बेगूसराय लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था। लेकिन सफलता नहीं मिली।

संगठन में भी उनका योगदान रहा है। वे महामंत्री और प्रदेश महिला कांग्रेस की दो बार अध्यक्ष रह चुकी हैं। चुनाव हार जाने के बाद भी इनका बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र में लगातार आना-जाना जारी रहा।

कार्यकर्ताओं से गहरा लगाव रखना और पार्टी संगठन को मजबूती प्रदान करना, इनकी खासियत है।

दूसरी बड़ी चर्चित सीट मटिहानी की मांग की गई है। यहां से कांग्रेस पार्टी दो बार विधानसभा का चुनाव जीत चुकी है। कांग्रेस पार्टी के मौजूदा जिला अध्यक्ष अभय कुमार सार्जन का दावा सबसे ठोस माना जा रहा है। वे 2010 में इस सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। लेकिन पराजय हाथ लगी। सार्जन सिंह की इस क्षेत्र में और पार्टी संगठन में मजबूत पकड़ है। कांग्रेस अपने खाते में मटिहानी को शामिल कर

नतीजतन क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से इनका गहरा जुड़ाव बना रहा। और क्षेत्र पर भी मजबूत पकड़ बनी रही।

कार्यकर्ताओं का मानना है कि इस क्षेत्र से पूर्व विधायक अमिता भूषण को एक बार फिर से चांस मिलेगा, तो लड़ाई दिलचस्प होगी। अगर किसी कारण से अमिता भूषण का दावा कमजोर होता है, तो वैसी स्थिति में जिला के दो युवा तुर्क कांग्रेस नेताओं के नाम पर विचार करने की संभावना बढ़ेगी। इसमें बिहार प्रदेश शिक्षा मंच के प्रदेश अध्यक्ष व रतनपुर निवासी युवा नेता अभिषेक कुमार के नाम की जोर-दार चर्चा है। वे जिला के एक चर्चित विद्यालय सेंट जोसेफ पब्लिक स्कूल के निदेशक हैं। पार्टी के घोषित कार्यक्रम में इनकी प्रबल भागीदारी रही है। साफ सुथरा छवि के कारण ही यह भी प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं।

तीसरा नाम पोखरिया निवासी सुनील कुमार सिंह का आता है। वे कांग्रेस पार्टी के जिला महामंत्री हैं। इनका पुश्तैनी परिवार विगत सौ साल से कांग्रेस का झंडा बुलंद करता आया है। उनके पैतृक आवास सरयुग सदन में बिहार के कई मुख्यमंत्री व कई केंद्रीय मंत्री और पार्टी संगठन के दिग्गज नेताओं की आवाजाही होती रही है। पार्टी

पाती है, तो यहां भी चुनाव का नजारा काफी दिलचस्प होगा।

किसी कारण वश सार्जन का नाम यहां से हटता है, तो पार्टी के जिला उपाध्यक्ष सुबोध सिंह, रामानुज कुंवर मनियप्पा, मो. मतीन अख्तर के नाम पर विचार किया जा सकता है।ऐसी चर्चा आम है। वैसे मटिहानी विधानसभा सीट जिला की हॉट सीट मानी जाती है।

बछवाड़ा विधानसभा सीट पर भी मजबूत दावा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेश किया है। यहां लंबे समय तक कांग्रेसी विधायक रहे हैं। इस सीट पर बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष शिव प्रकाश उर्फ गरीबदास की ठोस दावेदारी बनती है। गरीब दास पूर्व मंत्री व सांसद डॉ. रामदेव राय के सपुत्र हैं। शिव प्रकाश ने 2020 के चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में बछवारा सीट से अपनी किस्मत आजमाई थी। और तकरीबन इकतालिस हजार वोट पाकर भी चुनाव हार गए। पराजय के बाद भी गरीबदास ने बछवाड़ा क्षेत्र का भ्रमण लगातार जारी रखा।

पार्टी के कार्यकर्ताओं और संभावित उम्मीदवारों की निगाहें आला कमान पर टिकी है। इसकी वजह भी साफ है। महागठबंधन में शामिल पांच घटक दलों में किसके खाते में कौन सी सीट आएगी, यह अभी किसी को नहीं मालूम।

कांग्रेस की इन दावेदारी वाले चार सीटों में बेगूसराय और बछवाड़ा के विधायक बीजेपी से हैं। मटिहानी से जेडीयू के विधायक हैं। और तेघरा लेफ्ट के हिस्से में है।

जनतादल यू चला बूथ स्तर की ओर: रूदल राय

बेगूसराय जिला जनतादल यू कार्यालय के कपूरी सभागार में जदयू जिलाध्यक्ष रूदल राय की अध्यक्षता में पार्टी के चार विधानसभा के प्रखंड अध्यक्ष एवं प्रकोष्ट अध्यक्ष की बैठक हुई। इस बैठक में पार्टी के जिला संगठन प्रभारी शिवनंदन सिंह, मटिहानी विधानसभा प्रभारी परशुराम पारस,तेघड़ा विधानसभा प्रभारी सुनील भारती, चेरियाबरियारपुर विधानसभा प्रभारी सुबोध पटेल,पूर्व मंत्री मंजू वर्मा, बेगूसराय नगर अध्यक्ष पंकज कुमार के साथ-साथ प्रखंड अध्यक्ष एवं प्रकोष्ट अध्यक्ष भी बैठक में मौजूद थे।

अध्यक्षीय संबोदन में रूदल राय ने कहा कि 21 जून से 25 जून तक पहले चरण में जनतादल यू बेगूसराय चार विधानसभा- मटिहानी, चेरियाबरियारपुर, तेघड़ा एवं साहेबपुरकमाल विधानसभा में यह अभियान चलाएगा। और सरकार के किए गए कार्यों की चर्चा करेगा। इस बूथ स्तर की बैठक में प्रखंड से जुड़े हुए पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी और जिला के पदाधिकारी सहित सभी सम्मानित साथियों को पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष आमंत्रित कर बूथ स्तर के साथियों के साथ बैठक करेंगे। एक दिन में दो पंचायत की बैठक होगी। समय 11 बजे 1 बजे तक। और दूसरी बैठक 2 बजे दिन 5 बजे दिन तक होगी।

इस बैठक में पार्टी के प्रवक्ता अरुण कुमार महतो, मिडियासेल अध्यक्ष मोनू पटेल, युवाध्यक्ष पंकज राय, प्रखंड अध्यक्ष चंदन कुमार, रामनरेश आजाद, शम्भू कुमार सिंह, मो. जियाउल्लाह, अनिल चौधरी, अबध शर्मा, अल्पसंख्यक अध्यक्ष मो. सरफराज, किसान अध्यक्ष सुरेश प्रसाद सिंह, छात्र अध्यक्ष भवानी कुमार,सतीश कुमार, पंकज राय, अभिनाश कुमार, हीरा लाल महतो सहित पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे।

हेल्थ इंस्टिच्युट में मना विश्वयोग दिवस समारोह

'आरोग्य भारती' की प्रांतीय शाखा के सौजन्य से बेऊर पटना स्थित संस्थान इंडियन इंस्टिच्युट ऑफ हेल्थ एडुकेशन ऐंड रिसर्च में, विश्व योग दिवस पर कार्यक्रम आयोजित हुआ। योग-कार्यक्रम का उद्घाटन संस्थान के निदेशक-प्रमुख डा अनिल सुलभ किया। योग पर अपनी राय रखते हुए उन्होंने कहा कि योगाभ्यास मनुष्य के तन और मन को स्वस्थ, सबल और ऊर्जावान बनाकर उसके जीवन को आनंदमय और मंगलकारी बना देता है। यह एक विशुद्ध वैज्ञानिक पद्धति है।

उन्होंने आगे कहा कि युवाओं को रात्रि का हल्का भोजन कर, यथा सांध्य शीघ्र सोना चाहिए। प्रातः काल सूर्योदय से घंटे भर पूर्व जग कर, प्राणायाम के साथ योगाभ्यास और ध्यान करना चाहिए। इससे जीवन की दशा और दिशा दोनों ही बदल जाएगी।

वरिष्ठ योगाचार्य पं. हृदय नारायण झा ने प्राणायाम और योगाभ्यास की विधियां बताकर सामूहिक योगाभ्यास कराया। उन्होंने कहा कि योग का नियमित अभ्यास मनुष्य के आंतरिक आनंद का विराट द्वार खोलता है। प्रत्येक व्यक्ति को इसका अभ्यास करना चाहिए।

आरोग्य भारती के प्रांतीय अध्यक्ष डा अशोक कुमार ने अतिथियों एवं योगाचार्य का स्वागत किया। संस्था के प्रांतीय सचिव डा गुरु शरण पाल, डा वी तिवारी, डा अजय शरण, डा केशव कुमार, सच्चिदानन्द एवं अमरेन्द्र कुमार ने भी अपने विचार रखे।

कार्यक्रम के दौरान संस्थान के संकायाध्यक्ष, छात्र कल्याण अहसास मणिकान्त, डा रूपाली भोवाल, डा नवनीत कुमार, प्रो मधु माला, डा संतोष कुमार सिंह, प्रो चंद्रा आभा, डा आदित्य ओझा, सूबेदार संजय कुमार, कुमार करुणानिधि, विनय कुमार, रवींद्र प्रजापति, बेबी कुमारी आदि बड़ी संख्या में संस्थान के शिक्षक, कर्मी एवं छात्रगण मौजूद थे।

ब्यूरो रिपोर्ट ग्लोबल ऑब्ज़र्वर

साहित्य सेवा समिति जमशेदपुर ने डॉ. हरिबल्लभ सिंह 'आरसी' का जन्म-दिन समारोह मनाया

16 जून, 2025 की शाम जमशेदपुर के लिए एक यादगार पल बनी। दरअसल इस दिन साहित्य और समाज सेवा में विराट वैभव का एहसास कराने वाले साहित्यकार और डॉ. श्रीकृष्ण सिन्हा संस्थान के महासचिव डॉ. हरिबल्लभ सिंह 'आरसी' का जन्म-दिन था। इस जन्म-दिन समारोह को साहित्य सेवा समिति, जमशेदपुर ने और भी यादगार बना दिया। साहित्य सेवा समिति ने डॉ. श्रीकृष्ण सिन्हा संस्थान के सभागार में उनका जन्म-दिन धूमधाम से मनाया।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रांची विश्वविद्यालय के पूर्व हिन्दी विभागाध्यक्ष,डॉ. जंग बहादुर पांडेय एवं विशिष्ट अतिथि कोल्हान विश्वविद्यालय के पूर्व हिन्दी विभागाध्यक्ष डॉ. लक्ष्मण प्रसाद थे। समारोह की अध्यक्षता वरिष्ठ साहित्यकार अरविंद विद्रोही ने की। और संचालन साहित्य सेवा समिति के महासचिव राजदेव सिन्हा ने किया। स्वागत भाषण सहित्य सेवा समिति के डॉ. श्यामलाल पांडेय ने दिया।

सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्पार्चन एवं माल्यार्पण से कार्यक्रम की शुरूआत हुई। हुआ। इसके बाद डॉ. हरिबल्लभ सिंह 'आरसी' का पुष्प गुच्छ एवं शॉल ओढ़ाकर स्वागत हुआ। मुख्य अतिथि प्रोफेसर (डॉ.) जंग बहादुर पांडेय एवं विशिष्ट अतिथि डॉ. लक्ष्मण प्रसादजी ने उन्हें सम्मानित किया।

इस अवसर पर विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों एवं सचिवों ने पुष्प गुच्छ देकर उन्हें सम्मानित किया। तुलसी भवन के मानद महासचिव प्रसेनजित तिवारी ने अपने कार्यकारी सदस्यों के साथ 'आरसी' जी को जन्म - दिन की शुभकामनाएं देते हुए सम्मानित किया।

पूर्व सैनिक सेवा परिषद के सुशील कुमार ने उन्हें पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया। श्रीकृष्ण पब्लिक के छात्र अर्णव भारद्वाज ने वाद्ययंत्र बजाकर समारोह में चार चांद लगा दिया। श्रीकृष्ण पब्लिक स्कूल की तीनों शाखाओं की प्राचार्या श्रीमती पूर्णिमा त्रिपाठी, श्रीमती कृष्णा पांडेय एवं श्रीमती पूजा किरण मुंडा ने पुष्प गुच्छ देकर उन्हें बधाई दी।

इस अवसर पर मुख्य अतिथि डॉ. जंग बहादुर पांडेय ने कहा कि सम्मान समारोह,जन्मदिन या जयंती उसी व्यक्ति की मनाई जाती है, जिसका समाज या राष्ट्र के लिए योगदान होता है। 'आरसी' जी के व्यक्तित्व में चार सिद्धांतों का समावेश है। समयनिष्ठता, न्यायप्रियता, सत्य के पथिक एवं अपनी लाभ-हानि की चिंता न कर छात्र और शिक्षकों के लाभ-हानि की चिंता करना।

उन्होंने आगे कहा कि अतिथियों का सम्मान करना इनके जीवन की विशेषता है। और यही इनके दीर्घजीवी होने का मूलमंत्र है।

विशिष्ट अतिथि प्रो. (डॉ.) लक्ष्मण प्रसाद ने कहा कि डॉ. श्रीकृष्ण सिन्हा संस्थान और संस्कार इनके व्यक्तित्व का पर्याय है। साहित्य, संस्कार और शिक्षा का समन्वय इनके कर्म क्षेत्र की विशेषता है। छात्र एवं छात्राओं की आर्थिक मदद करना, इनका स्वभाव है। ये साहित्य और शिक्षा के प्रति आजीवन समर्पित रहे हैं।

अपनी अध्यक्षता में वरिष्ठ साहित्यकार अरविंद विद्रोही ने कहा कि आरसीजी ने ट्रेड यूनियन के माध्यम से मजदूरों की समस्या का, जो समाधान किया है, वह जमशेदपुर शहर के लिए वरदान है।

साहित्य सेवा समिति के सचिव अरूणजय कुमार सिंह के धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ।

ग्लोबल ऑब्ज़र्वर
मतलब निर्भीक और निष्पक्ष
इस छोर से उस छोर तक
RNI NO. DELHIN/2016/71079

निर्भीक पत्रकारिता की जीती जागती मिसाल है ग्लोबल ऑब्ज़र्वर

आपके मन की बात होती है यहां साफ़गोई के साथ

सरकार की आलोचना इसलिए कि यह पत्रकारिता का धर्म है

आपकी क़लम को ताक़त
और आपको शोहरत दिलाने के लिए
एक अवसर लेकर आया है -
'ग्लोबल ऑब्ज़र्वर'। चाहते हैं अगर
आपकी ख़बरों का हो देशव्यापी असर तो
इस अवसर को लपक लें। अपना बायोडाटा
इस मेल पर भेजें:-

globalobserver@gmal.com